वर्ष 13 • अंक 42 • 8 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

गुरुवार 9 अप्रैल 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 3

मुख्य श्रेणी के विदेशी निवेशकों के लिए नियम हुए आसान

रणजय दत्ता पृष्ठ 2

जरूरी वस्तुओं की ढुलाई मुफ्त में करेगी इंडिगो

डॉलर रु. 76.30 ▲ 0.70 पैसे | यूरो रु. 82.90 ▲ 0.70 पैसे | सोना (10ग्राम) रु. 44710 ▲ 10 रुपये | सेंसेक्स 29894.00 ▼ 173.30 | निफ्टी 8748.80 ▼ 43.50 | निफ्टी फ्यूचर्स 8750.50 ▲ 01.80 | ब्रेंट क्रूड 26.60 डॉलर ▼ 0.20 डॉलर

एक नज़र

5 लाख रुपये तक लंबित कर राशि की तुरंत होगी वापसी

आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि वह करदाताओं को 5 लाख रुपये तक लंबित कर राशि की वापसी तुरंत करेगा। इससे करीब 14 लाख करदाताओं को लाभ होगा। सरकार कारोबारी इकाइयों को राहत देने के लिए लंबित 18,000 करोड़ रुपये जीएसटी और सीमा शुल्क वापसी भी जल्द करेगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया रस के कारण उत्पन्न स्थिति और कारोबारी इकाइयों को तुरंत राहत उपलब्ध कराने के लिए 5 लाख रुपये तक की राशि की लंबित सभी आयकर वापसी तुरंत करने का निर्णय किया गया है।

1.6 प्रतिशत विकास दर का अनुमानः गोल्डमैन सैक्स

वैश्विक शोध संस्था गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ सकती है और कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर ऋणात्मक 1.8 फीसदी रह सकती है। इसके साथ ही भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020-21 में 1.6 फीसदी रह सकती है। पहले इसके 3.3 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि यह अब भी अमेरिका की वृद्धि दर से अधिक है, क्योंकि शोध एजेंसी ने वहां की जीडीपी वृद्धि दर ऋणात्मक 6.2 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। पृष्ठ 3

मारुति ने मार्च में 32 प्रतिशत घटाया उत्पादन

देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजूकी ने मार्च महीने में उत्पादन में 32.05 प्रतिशत की कटौती की है। कंपनी ने कहा कि उसने इस साल मार्च में 92,540 वाहनों का उत्पादन किया जबकि साल भर पहले उसने 1,36,201 वाहनों का उत्पादन किया था। इस दौरान यात्री वाहनों का उत्पादन साल भर पहले की 1,35,236 कारों की तुलना में 32.26 प्रतिशत कम होकर 91,602 कार रह गई। ऑल्टो, एस-प्रेसो, वैगनआर, सेलेरियो, इग्निस, स्विफ्ट, बलेनो और डिजायर समेत मिनी व कॉम्पेक्ट श्रेणियों में उत्पादन इस दौरान मार्च 2019 के 98,602 वाहनों की तुलना में 31.33 प्रतिशत कम होकर मार्च 2020 में 67,708 वाहनों पर आ गया।

आईआरडीए ने भी सावधि ऋण टालने की दी अनुमति

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तर्ज पर बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने भी बीमा कपंनियों को उनके द्वारा आवंटित सावधि ऋणों पर भुगतान की किस्तें तीन महीने तक नहीं लेने की इजाजत दी है। यह प्रावधान 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 के बीच ऋणों की किस्तों पर लागू होगा। बीमा नियामक ने कहा कि ऐसे ऋणों की भुगतान अवधि और शेष बचीं किस्तें तीन महीने के लिए आगे बढ़ जाएंगी।

2020 में विश्व व्यापार में आएगी एक तिहाई कमी

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने बुधवार को कहा कि कोरोनावायरस से मचे उथलपुथल से वर्ष 2020 में विश्व व्यापार में एक तिहाई तक की कमी आ सकती है। डब्ल्यूटीओ के अनुसार इस वर्ष वैश्विक स्तर पर व्यापार के आंकडे काफी खराब रहने वाले हैं। संस्था के अनुसार 2020 में विश्व व्यापार का आंकड़ा 13 से 32 प्रतिशत कम रह सकता है। डब्ल्यूटीओ ने एक बयान में कहा कि वायरस की वजह से पूरी दुनिया में सामान्य आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित होंगी।

बंदी बढ़ेगी, इलाके होंगे सील

प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक में सभी दल लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली/लखनऊ, 8 अप्रैल

कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में सभी राजनीतिक दलों के बीच आम राय बनाने के प्रयास में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि देश में कोरोनावायरस के कारण सामाजिक आपातकाल जैसे हालात हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल से आगे बढ़ाई जा सकती है।

मोदी ने विपक्षी दलों और संसद के अन्य दलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई बैठक में कहा कि वह 11 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में फैसला करेंगे। एक सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि कई राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और विशेषज्ञों ने लॉकडाउन बढ़ाने के सुझाव दिए हैं।

पिछले सप्ताह मोदी ने चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाने की बात कही थी। पिछले कुछ दिनों में कई राज्य सरकारों ने इस मामले में अपने सुझाव दिए हैं, जिनमें विशेष रेलगाड़ियां चलाना और कुछ औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति देना शामिल हैं।

महाराष्ट्र जैसे ज्यादा प्रभावित राज्यों ने आशंका जताई है कि लॉकडाउन हटने से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का कहना है कि

राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही को शुरू नहीं किया जाना चाहिए।

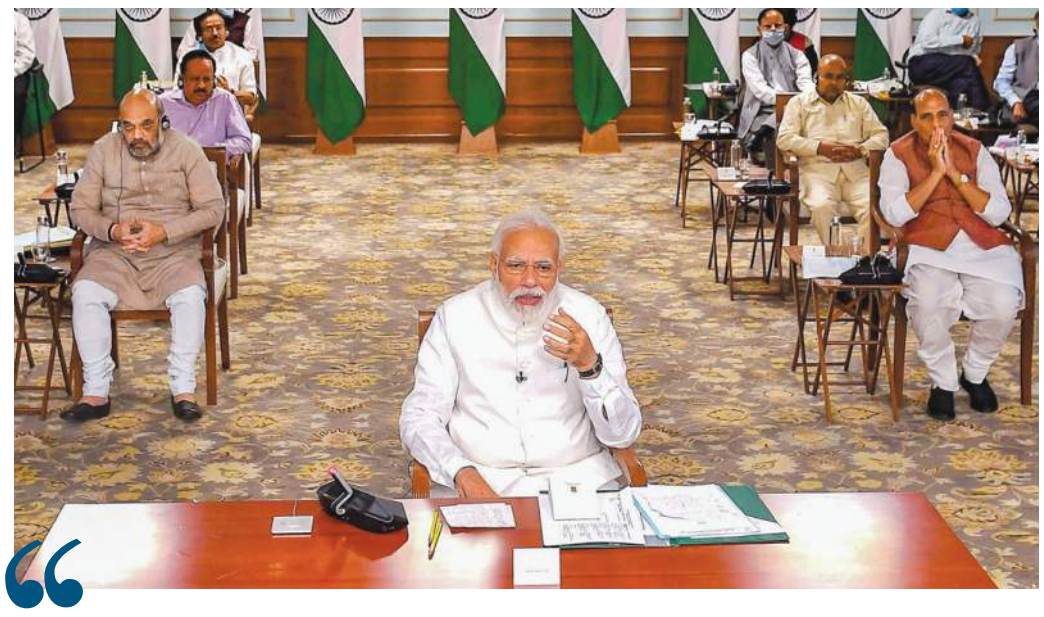

सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड-19 से पहले और इसके बाद की जिंदगी एक जैसी नहीं होगी

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

छत्तीसगढ़ में कोरोनावायरस के कम मामले हैं और उसे आशंका है कि दूसरे राज्यों से लोगों के आने से इनमें इजाफा हो सकता है। करीब चार घंटे तक चली बैठक के बाद कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि करीब 80 प्रतिशत नेताओं ने प्रधानमंत्री को सुझाव दिया कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। आजाद ने कहा कि वह भी इसके पक्ष में हैं। इस बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वह राज्य के 15 जिलों में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों के 14 अप्रैल की रात से सील कर देगी। इन जिलों में दिल्ली से सटे गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर भी शामिल हैं। इसके अलावा इस सूची में आगरा, लखनऊ, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, कानपुर, बस्ती, फिरोजाबाद, सहारनपुर, महाराजगंज और सीतापुर शामिल हैं। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विभिन्न दलों के नेताओं के साथ मौजूदा हालात पर विचार-विमर्श किया। *फोटोः पीटीआई*

इन जिलों में 81 थाना क्षेत्रों के तहत कुल 101 इलाके चिह्नित किए गए हैं। सख्ती से लॉकडाउन लागू कराने के लिए पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी और लोगों को घर पर जरूरी चीजों की आपूर्ति की जाएगी। राज्य में कोविड-19 के मामले बढ़कर 343 हो गए हैं, जिनमें 187 मामले तबलीगी जमात के जलसे से जुड़े हैं। ■ शेष पृष्ठ 8

घटती मांग हिलाएगी आवासीय डेवलपरों की बुनियाद

राघवेंद्र कामत
मुंबई, 8 अप्रैल

- कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से मांग में आई कमी
- डेवलपर नई परियोजनाएं शुरू करने से भी कर रहे परहेज
- मकानों के दाम घटने की भी जताई जा रही है आशंका
- बढ़ रही है बिना बिके मकानों की संख्या

कोरोना संकट का असर देश के रियल्टी क्षेत्र पर पड़ता दिख रहा है। देश की प्रमुख रियल्टी कंपनी मुंबई के हीरानंदानी समूह के प्रबंध निदेशक निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि लॉकडाउन की घोषणा के बाद से हमने गिने-चुने सौदे ही किए हैं। कंपनी की अपनी ऑनलाइन रिस्पॉन्स टीम भी है जो मौजूदा समय में आवासीय संपत्तियों की ऑनलाइन बिक्री करने का प्रयास कर रही है।

मुंबई के एक अन्य डेवलपर ने कहा कि 1 अप्रैल के बाद से बिक्री में भारी गिरावट आई है। उन्होंने कहा, 'अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम साल के इस समय अच्छी बिक्री कर सकते थे।'

रनवाल समूह के निदेशक संदीप रनवाल ने कहा कि कंपनी डोंबीवली, पर्ले और ठाणे इलाके में ऑनलाइन बिक्री कर रही है। उन्होंने कहा, 'हमने वादा किया गया है कि अगर कीमतें घटती हैं तो हम भी उनसे उतने ही दाम लेंगे।' संपत्ति सलाहकारों का कहना है कि हम ग्राहकों से कह रहे हैं कि वे परियोजनाएं देखें और खरीदें। लॉकडाउन के बाद से आवासीय संपत्तियों की बिक्री में गिरावट का यह अकेला मामला नहीं है। पिछले 15 दिन से आवासीय संपत्तियों की बिक्री में भारी गिरावट आई है और पूरे साल मांग में सुधार होने की उम्मीद कम ही है। मुंबई के डेवलपरों की संस्था क्रेडाई-एमसीएचआई के अनुसार इस साल फरवरी से मार्च के दौरान बुकिंग में करीब 80 फीसदी की गिरावट आई है। संपत्ति सलाहकारी जेएलएल इंडिया के मुताबिक प्रॉपर्टी चालू कैलेंडर वर्ष की मार्च तिमाही में देश के प्रमुख शहरों में संपत्तियों की बिक्री में करीब 30 फीसदी की गिरावट आई है।

पिछले पांच साल में आावासीय संपत्तियों की बिक्री में यह दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले नोटबंदी के दौरान 2017 की पहली तिमाही में बिक्री 37 फीसदी घटी थी। जेएलएल ने कहा किक 2019 की पहली तिमाही में बेंगलूरु में सबसे ज्यादा बिक्री हुई थी जबकि 2020 की पहली तिमाही में सबसे ज्यादा 52 फीसदी बिक्री इसी शहर में घटी है। डेटा विश्लेषक फर्म प्रॉपइक्विटी के अनुसार 2020 की पहली तिमाही में मकानों की बिक्री 27 फीसदी घटी है और नई परियोजनाओं में भी 39 फीसदी की कमी आई है।

एक अन्य ब्रोकरेज फर्म एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स ने कहा कि इस साल मकानों की बिक्री 25 से 35 फीसदी घट सकती है जबकि नई परियोजनाओं में भी 25 से 30 फीसदी की कमी आ सकती है। मुंबई की फंड मैनेजर फर्म एएसके समूह के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी सुनील रोहकाले ने कहा, 'सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग बड़ी खरीदारी की योजना पर पुनर्विचार कर रहे हैं। वे देखो और इंतजार करो की रणनीति अपना रहे हैं।' उन्होंने कहा कि लागे अब नौकरी, घर के बजट, मासिक भुगतान की देनदारियों जैसी प्राथमिकताओं पर ध्यान दे रहे हैं। जेएलएल के अनुसार डेवलपरों के पास काफी ज्यादा अनबिके मकान भी हैं।

निजी लैब ऊंची कीमत न वसूलें

सोहिनी दास/एजेंसी
मुंबई/नई दिल्ली, 8 अप्रैल

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि केंद्र सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कोविड-19 की जांच करने वाले निजी लैबोरेटरीज आम लोगों से अतिरिक्त शुल्क न वसूल सकें। इसके साथ ही सरकार को आम लोगों को इन लैबों द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क वापस करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और एस रवींद्र भट्ट के पीठ ने वकील शशांक देव सुधि की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें कहीं। सुधि ने अपनी याचिका में मांग की थी कि अदालत केंद्र और संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश दे कि देश के सभी नागरिकों के लिए कोविड-19 की जांच मुफ्त में उपलब्ध कराए। सुधि ने पीठ को बताया कि लैबों द्वारा कोविड-19 की जांच मुफ्त में की जानी चाहिए। इस पर सुनवाई करते

- अदालत ने केंद्र को ऐसी व्यवस्था बनाने को कहा जिससे निजी लैब ज्यादा शुल्क न वसूल सकें
- जांच शुल्क की प्रतिपूर्ति करने का भी उपाय तलाशने के दिए निर्देश
- डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा साधन मुहैया कराने का निर्देश

हुए पीठ ने सुझाव दिया कि केंद्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निजी लैबोरेटरियां जांच का ज्यादा शुल्क न वसूले और सरकार को इस शुल्क की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था करनी चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि वह इस मामले में आदेश दे सकता है।

कोविड-19 की जांच करने वाली निजी लैबोरेटरियों का मानना है कि अगर समुचित व्यवस्था हो तो जांच नि.शुल्क या कम लागत में की जा सकती है। मुंबई में रोजाना करीब 250 नमूनों की जांच करने वाले थायरोकेयर के संस्थापक एवं चेयरमैन ए वेलूमणि ने कहा कि जांच प्रक्रिया को सुगम और तेज बनाने के लिए दो या तीन अलग एजेंसियां नियुक्त करने की जरूरत है।

उनका मानना है कि नमूना संग्रह करने के लिए एक नोड एजेंसी हो सकती है। अभी निजी लैब नमूना लेने के लिए निजी एजेंसियों का सहारा लेते हैं। सरकार द्वारा देश भर में ऐसी करीब चार से आठ नमूना संग्रह करने वाली एजेंसियां नियुक्त की जा सकती है।

5,274 मामले 149 की मौत

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोनावायरस के संक्रमण के मामले बुधवार को बढ़कर 5,274 हो गए, जिनमें पिछले 24 घंटों के दौरान 485 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय के अनुसार इस महामारी से अब तक मरने वालों की संख्या 149 हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 4,714 है, जबकि 410 लोग ठीक हो चुके हैं और एक मरीज दूसरी जगह भेजा गया है। कुल आंकडों में 71 विदेशी नागरिकों के मामले भी शामिल हैं।

मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 25 नई मौत हुई हैं। इनमें महाराष्ट्र में 16, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और तमिलनाडु में 2-2 और आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति की मौत शामिल है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 64 मौत हुई हैं। ■ पृष्ठ 8

कोविड बाद के दौर के लिए तैयार हो रहीं कंपनियां

सुरजीत दास गुप्ता, सुदीप्त दे, शैली मोहिले और अर्णव दत्ता
नई दिल्ली, 8 अप्रैल

भारतीय विनिर्माण कंपनियां कोविड-19 के कारण पैदा हुई नई परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। इस महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है और इसके हटने के बाद उन्हें अपने कामकाज के तौर-तरीकों में कई बुनियादी बदलाव करने होंगे।

इन कंपनियों का कहना है कि उनकी दुनिया अब पूरी तरह बदली हुई होगी। नए तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए उनकी सरकार के साथ बातचीत चल रही है। बड़े कारखानों में कामगारों को फ्यूमिगैशन चैंबरों से गुजरना होगा, जहां उनके पूरे शरीर पर दवा का छिड़काव होगा। इसके बाद ही उन्हें कारखाने में जाने दिया जाएगा। कारखाने तक ले जाने वाली बसों में ही सबसे पहले कामगारों की कोविड-19 की जांच की जाएगी। उनके शरीर का तापमान मापने के लिए इन बसों में डिजिटल थर्मामीटर की व्यवस्था होगी। सामाजिक दूरी के लिए बस में बाजू वाली सीट खाली रखी जाएगी। विमान यात्रा के लिए भी यह व्यवस्था होगी। वाहन क्षेत्र के की संस्था ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसीएमए) अपने सदस्यों के लिए इस तरह के सुझाव पर विचार कर रही है।

विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों के सभी मुख्य कार्याधिकारी इस बात से सहमत हैं कि सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरुआत में स्वचालन (ऑटोमेशन) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग बढ़ेगा। मारुति सुजूकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा, 'पहले सुरक्षा पर जोर था ताकि दुर्घटनाएं कम से कम हों, लेकिन अब स्वास्थ्य पर जोर होगा। कामगारों को वायरस से बचाने की पूरी कोशिश होगी ताकि एक भी कामगार इससे संक्रमित न हो। मानक परिचालन प्रक्रिया में बुनियादी बदलाव होगा।'

- बसों में तापमान की होगी जांच, बस में बगल की सीट होगी खाली
- कारखाने में प्रवेश करने से पहले फ्यूमिगैशन चैंबर से गुजरना होगा
- ज्स्वचालन पर होगा जोर, बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी
- कुछ विशेष कार्यों के लिए पीपीई का इस्तेमाल
- हर पाली में होगी संयंत्र की साफ- सफाई

वाहनों के लिए पेंट्स बनाने वाली कंपनी निप्पन पेंट्स इंडिया ने दो पालियों के बीच कामगारों के मध्य किसी भी तरह के संपर्क को रोकने के लिए 12 सूत्री एक एजेंडा बनाया है। इसके तहत सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखा जाएगा और पेशेवर एजेंसियों से संयंत्र की साफ- सफाई तथा दवा का छिड़काव किया जाएगा। साथ ही कंपनी एक स्वघोषित फॉर्म भी तैयार कर रही है, जिसमें कर्मचारियों के रोजाना अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देनी होगी। साथ ही वह कूलरों से पानी निकालने जैसे कामों के लिए विशेष सुरक्षा उपकरण भी खरीद रही है। इनके अलावा थर्मल स्कैनरों की भी व्यवस्था की जा रही है। इस जापानी कंपनी के प्रेजिडेंट शरद मल्होत्रा ने कहा, 'इनमें से कुछ तौर-तरीके तब तक जारी रहेंगे जब तक कोरोनावायरस पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता है। बाकी मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) का हिस्सा बन जाएंगे। उत्पादकता बढ़ाने के लिए ऑटोमैशन का भी व्यापक इस्तेमाल किया जाएगा।'

कंपनियां अपने संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। श्रीराम पिस्टंस ऐंड रिंग्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी अशोक तनेजा ने कहा कि एसीएमए ने एक प्रोटोकॉल जारी किया है और कंपनियां भी अपने प्रोटोकॉल पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, 'इसमें संयंत्र की साफ-सफाई से लेकर भीड़भाड़ से बचने के तौर-तरीके शामिल होंगे। लेकिन संयंत्र में सभी के लिए भारी संख्या में मास्क लाना एक चुनौती है, जिस पर हम काम कर रहे हैं। एसीएमए केअधिकारियों का कहना है कि वे उद्योग के लिए एक विस्तृत प्रोटोकॉल पर काम कर रहे हैं जो एकाध दिन में तैयार हो जाएगा।

एफएमसीजी क्षेत्र की बात करें तो वाई वाई ब्रांड से नूडल बनाने वाली कंपनी सीजी कॉर्प ग्लोबल को सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्षमता कम करनी पड़ी है। कंपनी के देश में 10 संयंत्र हैं और वह कम क्षमता के साथ उत्पादन कर रही है। ■ शेष पृष्ठ 2

व्यापार गोष्ठी

कोरोना की मार से कैसे बचें छोटे उद्योग?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरु हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201 या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या अर्थव्यवस्था अधिक दिनों तक लॉकडाउन झेलेन में है सक्षम

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**

आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या लॉकडाउन को आगे बढ़ाना सही कदम होगा — हां **90.91%**, नहीं **09.09%**

खबरों में रहे स्टॉक

बंधन बैंक

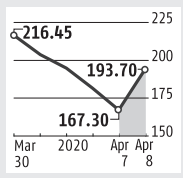

ए समूह में सबसे अधिक चढ़ने वाला शेयर

₹ 167.30 पिछला बंद भाव
₹ 193.70 आज का बंद भाव

▲ 15.78 %

अदाणी ग्रीन एनर्जी

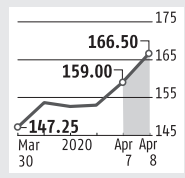

सौर ऊर्जा संयुक्त उद्यम में टोटाल एसए करेगी 3,707 करोड़ रु. का निवेश

₹ 159.00 पिछला बंद भाव
₹ 166.50 आज का बंद भाव

▲ 4.72 %

ग्रैन्यूल्स इंडिया

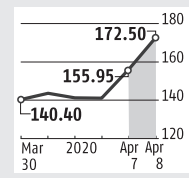

विशाखापत्तनम इकाई को ईयू जीएमपी से मंजूरी

₹ 155.95 पिछला बंद भाव
₹ 172.50 आज का बंद भाव

▲ 10.61 %

टीसीएस

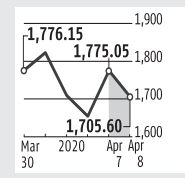

लॉकडाउन के कारण मार्च तिमाही की आय पर प्रभाव पड़ने की आशंका

₹ 1,775.05 पिछला बंद भाव
₹ 1,705.60 आज का बंद भाव

▼ 3.91 %

सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज

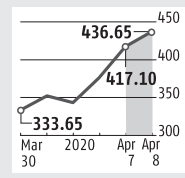

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में सबसे अधिक चढ़ने वाला शेयर

₹ 417.10 पिछला बंद भाव
₹ 436.65 आज का बंद भाव

▲ 4.69 %

संक्षेप में

भारती एक्सा के एमडी एवं सीईओ बने राजा

भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने पराग राजा को कंपनी का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। कंपनी ने बुधवार को बयान में कहा कि इस नियुक्ति के लिए भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की मंजूरी ली जाएगी। राजा 30 अप्रैल, 2020 के बाद पदभार संभालेंगे। वह विकास सेठ का स्थान लेंगे, जो पिछले ढाई साल से कंपनी की अगुवाई कर रहे थे। भारती एंटरप्राइजेज (फाइनैंशियल सर्विसेज) के प्रबंध निदेशक राजेश सूद ने कहा कि पराग का वित्तीय सेवाओं के कारोबार का गहरा अनुभव है और हमें पूरा विश्वास है कि इसका कंपनी को बड़ा लाभ होगा। *भाषा*

तीन महीने में पैसा लौटाएं नीसा टेक के निदेशक

बाजार नियामक सेबी ने नीसा टेक्नोलॉजीज और उसके आठ निदेशकों को आदेश दिया है कि वे निवेशकों से कथित रूप से लिए गए धन को तीन महीनों के भीतर लौटाएं। उन्हें प्रतिभूति बाजार से कम से कम चार साल के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। सेबी ने कहा है कि यह धन 15 प्रतिशत वार्षिक की दर के ब्याज सहित लौटाया जाए। *भाषा*

दवाओं की बिक्री में दमदार वृद्धि

मार्च में घबराहट में की गई खरीदारी से दवाओं की बिक्री 9 फीसदी बढ़ी

सोहिनी दास
मुंबई, 8 अप्रैल

देशव्यापी लॉकडाउन के कारण देश भर में दवाओं के वितरण में व्यवधान के बावजूद मार्च में दवाओं की बिक्री में 8.9 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। प्रमुख श्रेणियों में ग्राहकों द्वारा घबराहट में की गई खरीदारी से बिक्री को रफ्तार मिली।

उदाहरण के लिए, हृदयरोग उपचार की दवाओं की बिक्री मार्च में 19.8 फीसदी बढ़ गई जबकि फरवरी में 11 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी। इसी प्रकार मधुमेहरोधी दवा श्रेणी में महीने के दौरान 18.2 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई जबकि एक महीना पहले यह आंकड़ा 11 फीसदी रहा था। कोरोनावायरस वैश्विक महामारी फैलने के कारण श्वसन संबंधी बीमारियों की दवा श्रेणी में करीब 23 फीसदी की दमदार वृद्धि दर्ज की गई।

हालांकि त्वचा रोग, स्त्री रोग, टीका आदि कुछ श्रेणियों की दवाओं की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। इन श्रेणियों में आमतौर पर डॉक्टरों के ताजा परामर्श के आधार पर खरीदारी की जाती है। इसके अलावा पेट की बीमारी, दर्द निवारक एवं विटामिन जैसी कुछ अन्य श्रेणियों में दवाओं की बिक्री में महीने के दौरान एकल अंक में वृद्धि दर्ज की गई।

मुंबई की एक प्रमुख दवा कंपनी के प्रमुख (हृदयरोग एवं मधुमेह इकाई) ने कहा कि वितरण एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। उन्होंने कहा, 'आमतौर पर एक महीने के दौरान होने वाली बिक्री के मुकाबले हमारी बिक्री लगभग 80 से 85 फीसदी रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन के कारण लॉजिस्टिक संबंधी व्यवधान की वजह से स्टॉकिस्ट और वितरक हमारे उत्पादों को लेने में असमर्थ थे। सीऐंडएफ एजेंटों ने अनुरोध किया कि हमें उत्पादों की अधिक आपूर्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि गोदामों से दवाओं के वितरण के लिए आवाजाही मुश्किल थी।' इसके बावजूद ग्राहकों द्वारा घबराहट में की गई खरीदारी के कारण बिक्री बढ़ गई। हृदयरोग एवं मधुमेह जैसी श्रेणियों में रोगियों ने घबराहट में दवाओं का स्टॉक जमा कर लिया। उन्होंने कहा कि मार्च में लगभग पूरे महीने मेडिकल रिप्रजेंटेटिव को अस्पतालों में नहीं जाने दिया गया। जबकि अचानक की गई देशव्यापी लॉकडाउन के कारण सभी तरह की आवाजाही थम सी गई।

जहां तक कंपनियों का सवाल है तो इप्का ने मार्च में 20.9 फीसदी की वृद्धि दर्ज की। उसके बाद टॉरंट फार्मा की बिक्री 16.2 फीसदी और अजंता फार्मा की बिक्री 15.2 फीसदी रही। वॉकहार्ट और बायोकॉन ने महीने के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

पिछले महीने घरेलू दवा बाजार में सुधार हुआ और वृद्धि 1 अंक से बढ़कर 12.1 फीसदी हो गई। इसे श्वसन रोग एवं संक्रमणरोधी दवा श्रेणियों में दमदार से बल मला। वास्तव में फरवरी के दौरान 10 शीर्ष उपचार श्रेणियों में से 8 में 10 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।

भारतीय दवा बाजार का आकार मूविंग एनुअल टर्नओवर (मैट) के आधार पर मार्च में 9.8 फीसदी की वृद्धि के साथ 1.43 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

दवाओं की बिक्री

मार्च में प्रमुख चिकित्सा

चिकित्सा	मार्च में वृद्धि दर (फीसदी में)
श्वसन रोग	22.2
हृदय रोग	19.9
मधुमेहरोधी	18.2
संक्रमणरोधी	10.2
मूत्ररोग	10.5

स्रोतः एआईओसीडी आवाक्स

जरूरी वस्तुओं की ढुलाई मुफ्त में करेगी इंडिगो

अरिंदम मजूमदार
नई दिल्ली, 8 अप्रैल

- इंडिगो ने सरकार से मांगी इस बारे में अनुमति
- अन्य निजी विमानन कंपनियां वाणिज्यिक आधार पर कार्गो का कर रही हैं परिचालन
- हवाई मार्ग से करीब 70 फीसदी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एयर इंडिया, अलायंस एयर और वायु सेना द्वारा किया जा रहा है

देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो ने सुदूरवर्ती इलाकों में खाद्य पदार्थों और दवाओं की आपूर्ति के लिए राहत उड़ान संचालित करने का प्रस्ताव दिया है। कंपनी के बेड़े में 259 विमान हैं। इंडिगो के मुख्य कार्याधिकारी रणजय दत्ता ने कहा कि कंपनी ने यह सुविधा नि:शुल्क मुहैया कराने की पेशकश की है।

सरकार ने इंडिगो को 30 राहत उड़ानें (रिलीफ फ्लाइट) संचालित करने के लिए अधिकृत किया है लेकिन दत्ता ने कहा कि विमानन कंपनी ऐसी और उड़ाने संचालित करना चाहती है और इसके लिए सरकार से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

इंडिगो के बेड़े में 219 एयरबस ए320 विमान और 25 छोटे आकार के एटीआर-72 जेट हैं, जो दूर-दराज के इलाकों में उड़ान भरने के लिए मुफीद हैं। कंपनी देश में 63 गंतव्यों के लिए उड़ानें संचालित करती हैं, जिनमें पूर्वोत्तर के छह राज्य भी शामिल हैं।

यात्री विमानों का परिचालन बंद हैं, ऐसे में इंडिगो चाहती है कि उसके बेड़े का इस्तेमाल देश भर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में किया जाए। दत्ता ने कहा, 'महामारी जैसे संकट की स्थिति में आपातकालीन दवाओं की आपूर्ति के लिए मालवहन शुल्क वसूलना इंडिगो के लिए मुनाफा कमाने का जरिया नहीं हो सकता। कंपनी इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं वसूलेगी।' उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए वंदे मातरम दिखाने का क्षण है।

लॉकडाउन की वजह से जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में कमी के बीच देश भर में आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए विमानन नियामक डीजीसीए ने पिछले हफ्ते यात्री विमानों को कार्गो सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी थी। हालांकि सरकार के पास आर्थिक तंगी है, ऐसे में वह सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन ककंपनी एयर इंडिया और अलायंस एयर से ही मालवहन का काम करा रही है। नागर विमानन सचिव प्रदीप सिंह खेराला ने कहा, 'एयर इंडिया और अलायंस एयर न्यूनतम लागत में कार्गो का संचालन कर रही है, जो केवल इन विमानों के संचालन की लागत भर है।'

सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 70 फीसदी कार्गो उड़ानों का संचालन एयर इंडिया, अलायंस एयर और वायु सेना के द्वारा किया जा रहा है। निजी क्षेत्र की कंपनी स्पाइसेज, ब्ल्यूडार्ट भी कार्गो ढो रही है लेकिन वह ऐसा वाणिज्यिक आधार पर कर रही है। हालांकि इंडिगो ने कार्गो ढुलाई मुफ्त में करने की पेशकश की है। दिसंबर 2019 तक इंडिगो के पास करीब 9,500 करोड़ रुपये की नकदी थी और संकट के समय में यह विमानन कंपनी सबसे बेहतर स्थिति में है।

बायोकॉन को अमेरिका में मिलेगी ताकत

उज्ज्वल जौहरी
मुंबई, 8 अप्रैल

पिछले दिनों एक ओर जहां प्रमुख सूचकांकों में 6.4 फीसदी की गिरावट आई, वहीं दूसरी ओर बायोकॉन का शेयर इस अवधि में 8 फीसदी चढ़ने में कामयाब रहा। कंपनी को मलेशिया में इंसुलिन निर्माण इकाई के लिए जांच के बाद अमेरिकी दवा नियामक से ईआईआर मंजूरी मिलने की वजह से शेयर में यह बढ़त दर्ज करने में मदद मिली है। ईआईआर एक प्रमुख जांच रिपोर्ट है जो अमेरिकी एफडीए द्वारा अपनी जांच पूरी होने पर दी गई है। इससे कंपनी को अमेरिका में इंसुलिन (ग्लेरगिन) की पेशकश एवं बिक्री के लिए मंजूरी का रास्ता साफ हुआ है।

इंसुलिन पेटेंट मिलना, मलेशियाई संयंत्र को हरी झंडी और ऑनकोलॉजी बायोसिमिलर आवेदन कंपनी के लिए सकारात्मक बदलाव हैं

कंपनी अपने भागीदार के साथ मिलकर हाल में अमेरिका में इंसुलिन ग्लेरगिन की पेटेंट लड़ाई पहले ही जीत चुकी है और उसके बाद उसने इस दवा को पेश करने के लिए आवेदन किया है। हालांकि विश्लेषक मलेशिया संयंत्र से संबंधित घटनाक्रम पर सतर्क बने हुए थे। यह मंजूरी अमेरिका तथा अन्य प्रमुख बाजारों में उसकी विकास संभावनाएं बढ़ाएगी। नियामकीय गतिरोध घटा है, क्योंकि कंपनी को हाल में बेंगलूरु में अपनी छोटी मॉलिक्यूल इकाई के लिए ईआईआर मिल गई है। इसका मतलब है कि छोटे मॉलिक्यूल व्यवसाय में विकास की गति बरकरार रहेगी।

इस बीच, माइलन और बायोकॉन ने भी अमेरिकी एफडीए के समक्ष अन्य ऑनकोलॉजी दवा एवास्टन (बिवैकीजुमाब) के बायोसिमिलर के लिए आवेदन किया है। आवेदन की समीक्षा 2020 के अंत तक पूरी हो जाएगी। विश्लेषकों का मानना है कि यह अमेरिका में बायोकॉन का तीसरा ऑनकोलॉजी बायोसिमिलर हो सकता है। दवा के 7 अरब डॉलर के वैश्विक बाजार के आकार को देखते हुए यह बायोकॉन के लिए एक बड़ा अवसर है।

बायोकॉन अमेरिका में कुछ समय पहले ऑनकोलॉजी दवा ट्रैस्टुजुमाब के लिए बायोसिमिलर ओगिव्री की बिक्री पहले ही शुरू कर चुकी है।

यह कंपनी के ऑनकोलॉजी बायोसिमिलर (पेगफिलग्रेस्टीम) की पेशकश से अलग है, जिसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। बेंगलूरु में कंपनी की नई निर्माण इकाई को पेगफिलग्रेस्टीम निर्माण के लिए अतिरिक्त मंजूरी मिली है, जिससे उसे अमेरिका और अन्य वैश्विक बाजारों में तेजी से बढ़ रहे बाजार अवसरों को पूरा करने में मदद मिलेगी। यही वजह है कि विश्लेषक कंपनी के परिदृश्य और संभावित मजबूत आय वृद्धि को लेकर सकारात्मक बने हुए हैं।

महामारी से निपटने के लिए पहल

आर कृष्णा दास
रायपुर, 8 अप्रैल

कोल इंडिया लिमिटेड की मुख्य इकाई साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने कोरोनावायरस महामारी के प्रसार से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, जिम्मेदार कॉरपोरेट सिटिजन होने के नाते एसईसीएल ने कोरबा जिला प्रशासन की सलाह पर तत्काल कदम उठाते हुए एहतियात के तौर पर अपने कर्मचारियों को 14 दिन घर में अलग-थलग रखा। सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी ने 83 कर्मचारियों को अलग-थलग रखा था जब उनमें से पांच ने कोरोनावायरस संक्रमित व्यक्ति के साथ प्रार्थना बैठक में हिस्सा लिया। कोरोनावायरस को रोकने के लिए एसईसीएल न सिर्फ अपने कार्यालयों को सैनिटाइज कर रही है बल्कि आसपास के इलाकों को भी। एसईसीएल ने अब तक जरूरतमंद लोगों को सैनिटाइजर व खाना और आवश्यक वस्तुओं के अलावा 64,536 मास्क का भी वितरण किया। प्रवक्ता ने कहा, अपने स्तर पर इस बीमारी को खत्म करने के लिए एसईसीएल हर मुमकिन कोशिश कर रही है और स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन के साथ सहयोग भी कर रही है। कंपनी ने कोरबा, बिलासपुर, सुरजापुर, बलरामपुर, अनुपूर, शहडोल और उमरिया जिला प्रशासन को 1.75 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भी दी है।

अभी सामान्य नहीं होगी उड़ान!

अरिंदम मजूमदार
नई दिल्ली, 8 अप्रैल

हवाई अड्डों पर कोई शुल्क मुक्त खरीदारी न होने से लेकर आधी क्षमता पर विमानों के उड़ान भरने के कारण लॉकडाउन बादकी अवधि विमानन क्षेत्र के लिए काफी कठिन होने जा रहा है। विमानन नियामक द्वारा तैयार किए जा रहे प्रोटोकॉल के अनुसार, कोरोनावायरस वैश्विक महामारी के खत्म होने के बाद भारतीय विमानन कंपनियों और हवाई अड्डों को सामाजिक दूरी के सख्त मानदंडों का अनुपालन करना पड़ेगा। विमानन कंपनियों को तब तक दिशानिर्देशों का पालन करना होगा जब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन इस संबंध में कोई स्पष्ट संकेत नहीं देता। अनुमानों से पता चलता है कि विमानन उद्योग को सेवाएं बहाल होने के बाद कई महीनों तक सख्त नियमों का पालन करना पड़ सकता है। समझा जाता है कि सरकार घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध को हटाएगी ताकि भीड़भाड़ को नियंत्रित किया जा सके।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा तैयार की जा रही मानक परिचालन प्रक्रिया के तहत सभी विमानन कंपनियों के लिए विमान में मध्य की सभी सीटों और अंतिम तीन कतारों को खाली रखना अनिवार्य होगा ताकि न्यूनतम संपर्क सुनिश्चित किया जा सके। इसका मतलब साफ है कि 186 सीटों वाले एयरबस ए320 जेट में केवल 106 सीटों के लिए ही बुकिंग की जा सकती है। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो एयरबस ए320 विमानों का परिचालन करती है।

- सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य हो सकती है
- विमान में बीच वाली सीटों को खाली रखा जा सकता है
- अंतिम तीन कतारों में सीटों को खाली रखा जाएगा
- न्यूनतम ऑन-बोर्ड सेवाओं की होगी अनुमति
- बोर्डिंग गेट और एयरोब्रिज पर भीड़भाड़ की होगी रोकथाम

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'विमान के भीतर सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए बीच की सीट को खाली रखना महत्त्वपूर्ण है। यदि उड़ान के दौरान किसी यात्री में लक्षण दिखते हैं तो उन्हें अलग करने के लिए अंतिम तीन कतारों की सीटों को भी खाली रखना होगा।'

केबिन क्रू और यात्रियों के बीच करीब संपर्क को रोकने के लिए विमानन कंपनियों को ऑन-बोर्ड सेवाओं को भी न्यूनतक करने के लिए कहा जाएगा। पहले से ही पैकेटबंद भोजन यात्रियों की सीटों पर उड़ान से पहले ही रख दिया जाएगा जबकि विमानन कंपनियां यात्रियों को खुद भोजन लाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं।

हवाई अड्डों पर भीड़भाड़ को रोकने के लिए विमानन नियामक एक व्यापक रणनीति तैयार कर रहा है। इसके तहत शुल्क-मुक्त बिक्री पर रोक सहित कई अन्य उपाय किए जाएंगे। अन्य उपायों में बोर्डिंग गेट या एयरोब्रिज पर एक समय में केवल तीन कतारों को अनुमति दी जाएगी। हवाई अड्डों को चेक-इन और सुरक्षा जांच के दौरान यात्रियों के बीच दो मीटर की दूरी सुनिश्चित करनी होगी।

एक अधिकारी ने कहा, 'खुले स्थानों पर सामाजिक दूरी को बनाए रखना आसान है। लेकिन विमान जैसे तंग स्थानों पर लोगों के बीच दूरी बनाए रखने के लिए कुछ उपाय करना आवश्यक होगा।' भारतीय हवाई अड्डों को सभी यात्रियों की थर्मल चेकिंग अनिवार्य तौर पर करने और ग्राहकों के संपर्क को सीमित करने के लिए कहा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'जब तक इस वायरस को नियंत्रित नहीं किया जाता तब तक कुछ समय के लिए सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है। हवाई अड्डों को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा जाएगा।'

उद्योग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार के सख्त नियमों के कारण विमानन कंपनियों के लिए परिचालन करना व्यावहारिक नहीं रह जाएगा और इससे किराये में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। हालांकि कमजोर मांग के कारण किराये में वृद्धि भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। विमानन सलाहकार फर्म सीएपीए के अनुसार, कोरोनावायरस प्रकोप के कारण भारतीय विमानन उद्योग को जून तिमाही में 3 से 3.6 अरब डॉलर का नुकसान होने की आशंका है।

नए कायदों के लिए तैयार हो रहीं कंपनियां

पृष्ठ 1 का शेष...

कंपनी के कार्यकारी निदेशक वरुण चौधरी ने कहा, 'हमने सभी आंतरिक बैठकें स्थगित कर दी हैं। बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी है और थर्मल स्कैनर लगाए हैं और कामगारों को कोविड-19 से बचने के लिए प्रशिक्षित किया है।'

सैमसंगए एलजी और फॉक्सकॉन जैसी मोबाइल हैंडसेट और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली कंपनियां पहले ही सरकार को बता चुकी हैं कि कोरोनावायरस संक्रमण से अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए वे क्या उपाय कर रही हैं। इनमें हर पाली में संयंत्र की साफ-सफाई दस्तानों और मास्क का अनिवार्य इस्तेमाल और स्थानीय अधिकारियों को हर कामगार के स्वास्थ्य की रिपोर्ट सौंपना शामिल है। भारत में कोडक और थॉमसन टीवी के उत्पाद बेचने वाली कंपनी सुपरप्लास्ट्रॉनिक्स के मुख्य कार्याधिकारी अवनीत सिंह मारवाह ने कहा, 'हम हर दो घंटे में थर्मल स्कैनिंग की योजना बना रहे हैं ताकि किसी भी जोखिम से बचा जा सके। इससे ऐसे लोगों की पहचान हो सकेगी जिसे बुखार है लेकिन वह दवा ले रहा है।' उद्योग की सरकार की तरफ से प्रोटोकॉल के दिशानिर्देशों का इंतजार है लेकिन सरकार ने अब तक इसे जारी नहीं किया है। वैश्विक ब्रांडों के लिए लिए मोबाइल उपकरण बनाने वाले जैना समूह के प्रबंध निदेशक प्रदीप जैन ने कहा, 'मैं थर्मल स्कैनर और दूसरे उत्पादों का ऑर्डर देना चाहता हूं, लेकिन मुझे सरकार की ओर से दिशानिर्देशों का इंतजार है। तब तक हम फ्यूमिगैशन चैंबर बना सकते हैं।' सवाल यह है कि इस तरह का प्रोटोकॉल जारी करने का अधिकार किसे है? जानकारों का कहना है कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को यह अधिकार प्राप्त है।

लॉकडाउन के बाद परिचालन बहाल करने की तैयारी

अदिति दिवेकर, अर्णव दत्ता और अमृता पिल्लई
मुंबई/नई दिल्ली, 8 अप्रैल

देसी विनिर्माण उद्योग उस दौर में परिचालन बहाल करने की तैयारी में जुट गया है जब कोरोनावायरस महामारी के प्रसार पर लगाम कसने के लिए हुआ 21 दिन का लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। लॉकडाउन की अवधि खत्म होने के बाद कंपनियों का ध्यान अपने उत्पादन का स्तर लॉकडाउन के पहले के स्तर पर लाने पर होगा।

सज्जन जिंदल की अगुआई वाली जेएसडब्ल्यू स्टील ने शुक्रवार को कहा था कि वह लॉकडाउन खत्म होने के बाद अपने सभी उत्पादन स्थल पर परिचालन बहाल करने की तैयारी कर रही है।

सैमसंग, एलजी, श्याओमी, गोदरेज, पैनासोनिक, ब्लू स्टार समेत सभी अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां कामकाज की बहाली की रूपरेखा तय करने के लिए अपने सभी हितधारकों और सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं, जिसकी निगरानी अधिकारप्राप्त मंत्रियों का समूह कर रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, सरकारी अधिकारियों ने उद्योग निकाय और विनिर्माताओं से कहा है कि विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने से जुड़ी प्रमुख चिंता और जरूरतें वह उनके सामने रखे। अधिकारप्राप्त मंत्रियों का समूह इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माताओं को उत्पादन शुरू करने की अनुमति देने पर जल्द बैठक कर सकता है।

लॉकडाउन के बावजूद पूरी क्षमता से काम कर रही जिंदल स्टील ऐंड पावर (जेसपीएल) धामरा, पारादीप, विजाग और गोपालपुर के उत्पादन का 80 फीसदी निर्यात कर रही है, जहां कामकाज चल रहा है। उसके सामने सबसे बड़ा अवरोध लॉजिस्टिक्स है।

जेएसपीएल के प्रबंध निदेशक वी आर शर्मा ने कहा, अभी ग्राहकों के पास माल भेजने के लिए ट्रक ड्राइवरों का अभाव बड़ी समस्या है। जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब ट्रक ड्राइवर काम पर लौट जाएंगे। उन्होंने कहा, देसी बाजार में हम अपने ग्राहकों को नजदीकी रेलवे स्टेशनों पर माल भेज रहे हैं और वे स्थानीय स्तर पर परिवहन की व्यवस्था कर माल अपने यहां ले जा रहे हैं।

उद्योग को कामगारों की वापसी, आपूर्ति श्रृंखला ठीक होने और इन्वेंट्री घटने की उम्मीद

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की ज्यादातर कंपनियों ने भी लॉजिस्टिक्स का मसला उठाया है क्योंकि कच्चा माल हासिल करने में किसी तरह की चिंता नहीं है क्योंकि चीन में उत्पादन इकाइयां पहले ही 70 फीसदी की क्षमता पार कर चुकी हैं। उद्योग ने मुंबई जैसे प्रमुख बंदरगाहों से माल तेजी से भेजने के लिए सरकार के सामने अपना पक्ष रखा है ताकि मुंबई बंदरगाह और उत्तर भारत की फैक्टरियों के बीच परिवाहन का समय दो दिन कम हो जाए। परिचालन शुरू करने को तैयार श्री सीमेंट ने भी ऐसी ही राय जताई है और कहा है कि श्रमिकों की अनुपलब्धता चिंता का विषय है। श्री सीमेंट के प्रबंध निदेशक एच एम बांगड़ ने कहा, हम तकनीकी तौर पर अपने संयंत्र शुरू करने के लिए तैयार हैं जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा।

जेके लक्ष्मी सीमेंट जैसी अन्य कंपनियों ने कहा कि वह लॉकडाउन खत्म होने पर स्पष्टता के आसपास उत्पादन दोबारा शुरू करने पर फैसला लेंगे। येस सिक्योरिटीज ने सीमेंट क्षेत्र के हितधारकों के साथ बातचीत के बाद एक नोट में कहा है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद परिचालन को पटरी पर लाने में कम से कम 15 दिन का समय लगेगा। उसके बाद रिकवरी धीरे-धीरे होने की संभावना है क्योंकि श्रमिकों के लौटने में लंबा वक्त लग सकता है।

गोदरेज अप्लायंसेज के कार्यकारी उपाध्यक्ष कमल नंदी के मुताबिक, कंपनी अपने कामगारों से लगातार संपर्क में है, जिनमें से कई देश भर में अलग-अलग जगह चले गए हैं। उन्होंने कहा, हम कर्मचारियों को वर्चुअल ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। वे सभी अलग-अलग व बिखरे हुए हैं और कई अपने गृह प्रदेश चले गए हैं।

फ्लेक्स, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और डिक्सन जैसी प्रमुख अनुबंध विनिर्माता 15 अप्रैल से उत्पादन बहाल करने पर जोर दे रही हैं। ब्लू स्टार के प्रबंध निदेशक बी त्यागराजन ने भी कहा कि उनका फर्म उत्पादन बहाल करने के लिए तैयार है।

मुख्य श्रेणी के विदेशी निवेशकों के लिए नियम हुए आसान

इस कदम से गैर-एफएटीएफ देशों मसलन मॉरीशस से निवेश बढ़ सकता है

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 8 अप्रैल

बाजार नियामक सेबी ने कैटिगरी-1 लाइसेंस के इच्छुक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए नियम आसान बना दिया है। इस कदम को शेयरों में विदेशी निवेश में इजाफे के तौर पर देखा जा रहा है। फाइनैंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) सदस्य देशों के बाहर वाले मुल्कों के निवेशक अभी भी ऐसे पंजीकरण के पात्र हो सकते हैं, अगर भारत सरकार उन देशों को निर्दिष्ट करती है। इस कदम से मॉरीशस व पश्चिम एशिया जैसे इलाकों के जरिये आने वाले फंडों व निवेशों को फायदा मिल सकता है और भारत में विदेशी निवेश बढ़ सकता है। यह मानना है विशेषज्ञों का।

अभी एफएटीएफ के 39 सदस्य हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन शामिल हैं। पश्चिम एशियाई देश मसलन बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत और यूएई इसके सदस्य नहीं हैं।

पिछले साल सितंबर में तीन श्रेणियों में वर्गीकरण के बाद करीब 80 फीसदी एफपीआई को कैटिगरी-1 यानी पहली श्रेणी में रख दिया गया। कैटिगरी-1 में रहने का मतलब अनुपालन का कम बोझ, सरल केवाईसी नियम और कम दस्तावेज की दरकार और निवेश पर काफी कम पाबंदी है। ऐसे निवेशक ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट सबस्क्राइब और जारी कर सकते हैं और प्रत्यक्ष हस्तांरण के प्रावधान में नहीं हैं।

पुनर्वर्गीकरण से पहले करीब तीन फीसदी एफपीआई ही कैटिगरी-1 का हिस्सा था और अधिकतर कैटिगरी-2 में शामिल थे। सिर्फ 13 फीसदी फंडों को ही कैटिगरी-3 में रखा गया था।

डेलॉयट इंडिया के पार्टनर राजेश गांधी ने कहा, यह कदम कैटिगरी-1 के तहत पात्र सूची का विस्तार एफएटीएफ सदस्य देशों से आगे करेगा। इसका मतलब ऐसे देशों से आने वाले एफपीआई के लिए न सिर्फ कम केवाईसी होगा बल्कि प्रत्यक्ष शेयर हस्तांतरण के नियमों से भी उन्हें छूट मिलेगी। गांधी ने कहा, एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव के अलावा इससे भी देश में निवेश लाने में मदद मिलेगी।

विशेषज्ञों ने कहा कि गैर एफएटीएफ देशों मसलन मॉरीशस और पश्चिम एशिया के देश अब इस विशिष्ट सूची में शामिल होने के लिए लॉबीइंग कर सकते हैं।

विल्सन फाइनैंशियल सर्विसेज की निदेशक नेहा मालवीय ने कहा, यह स्थापित तथ्य है कि कैटिगरी-1 में आने वाले एफपीआई फंडों की निवेशकों के बीच ज्यादा स्वीकार्यता है, इसी वजह से दुबई, केमन द्वीप और मॉरीशस जैसे देश भारत सरकार से छूट पाने की कोशिश करेंगे।

मॉरीशस, केमन द्वीप, साइप्रस और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से आने वाले ज्यादातर फंड अभी कैटिगरी-2 में वर्गीकृत हैं। भारत के साथ संधि में संशोधन के बावजूद मॉरीशस भारत में एफपीआई की रकम का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है।

नांगिया एंडरसन के पार्टनर सुनील गिडवानी ने कहा, यह पहला मौका है जब एफएटीएफ सदस्यों के अतिरिक्त सरकारी अधिसूचित देश भी कैटिगरी-1 में पंजीकरण के पात्र होंगे। मॉरीशस, केमन द्वीप और इंडोनेशिया गैर-एफएटीएफ देशों में अहम हैं, क्योंकि ये भारतीय शेयर बाजारों में द्वितीयक निवेश के लिहाज से प्रासंगिक हैं।

गिडवानी के मुताबिक, कैटिगरी-1 की पात्रता एफपीआई को परिचालन में काफी लचीलापन मुहैया कराएगा और उन्हें नए निवेशकों को आकर्षित करने में मदद भी करेगा। उन्होंने कहा, कैटिगरी-1 में पंजीकृत होने से एफपीआई के लिए भारतीय बाजार तक पहुंचने की प्रक्रिया प्रवेश समय में काफी आसान हो जाएगी क्योंकि उन्हें ऑफशोर ट्रांसफर टैक्स के प्रावधानों का अनुपालन करने की जरूरत नहीं होगी।

एफपीआई निवेश के लिए पांच अग्रणी देश

ऐसेट अंडर कस्टडी (लाख करोड़ रुपये)

देश	इक्विटी	डेट	कुल**
अमेरिका	10.39	0.58	11.02
मॉरीशस	3.63	0.38	4.02
लग्जमबर्ग	2.48	0.62	3.10
सिंगापुर	2.01	0.97	3.05
यूनाइटेड किंगडम	1.50	0.02	1.54

स्रोत : एनएसडीएल। 29 फरवरी, 2020 तक के आंकड़े
** हाइब्रिड फंड समेत

सुस्ती के दौर में नई पेशकशों से गोदरेज प्रॉपर्टीज को मिली मदद

राम प्रसाद साहू
मुंबई, 8 अप्रैल

जहां रियल एस्टेट क्षेत्र को कमजोर बिक्री और निर्माण गतिविधि में विलंब का सामना करना पड़ रहा है, वहीं गोदरेज प्रॉपर्टीज ने शानदार तिमाही बिक्री दर्ज की है। कंपनी के लिए बिक्री के साथ साथ वैल्यू के लिहाज से भी मार्च तिमाही शानदार रही। मार्च तिमाही में बुकिंग का आंकड़ा 2,380 करोड़ रुपये पर रहा जो अक्टूबर-दिसंबर की अवधि के आंकड़े का दोगुना और एक साल पहले की समान तिमाही के मुकाबले 10 प्रतिशत ज्यादा है।

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मुर्तजा अरसीवाला और सम्राट वर्मा का कहना है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए मजबूत व्यावसायिक रफ्तार बनी रहेगी, क्योंकि कंपनी ने मार्च तिमाही में पांच नई परियोजनाएं जोड़ीं जिसके साथ ही वित्त वर्ष 2020 में कुल परियोजनाओं की संख्या बढ़कर 10 हो गई है।

गोदरेज प्रॉपर्टीज द्वारा बेचे गए 3,000 मकानों में, 500 की बिक्री मार्च के दूसरे पखवाड़े (लॉकडाउन की अवधि भी शामिल) में हुई, क्योंकि कंपनी ने लॉकडाउन के बीच परिचालन बरकरार रखने के लिए डिजिटल माध्यम पर ध्यान केंद्रित किया। वित्त वर्ष 2020 के लिए आवासीय बिक्री सालाना आधार पर 14 प्रतिशत तक बढ़कर 5,840 करोड़ रुपये रही।

एडलवाइस सिक्योरिटीज के परवेज अख्तर काजी और आकाश दमानी का कहना है कि डिजिटल माध्यमों ने लॉकडाउन से जूझ रहे रियल्टी डेवलपरों को उम्मीद की किरण दिखाई है, क्योंकि ऐसे हालात में ग्राहक साइट विजिट नहीं कर पा रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसी कंपनियां डिजिटल साइट टूर्स, ईमेल डॉक्यूमेंट कन्फर्मेशन और वेरीफिकेशन पर ध्यान दे रही हैं जिससे सौदों के ऑनलाइन पूरा होने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है। शुरू में ओबरॉय रियल्टी और हीरानंदानी समूह ने भी कहा था कि उन्होंने कुछ सौदे ऑनलाइन के जरिये पूरे किए हैं।

जहां गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छी बिक्री करने में सक्षम रही है, वहीं मंदी से शोभा जैसी प्रतिस्पर्धियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बेंगलूरु की इस रियल्टी कंपनी ने मार्च तिमाही में 9 लाख वर्ग फुट की बिक्री दर्ज की जो एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 20 प्रतिशत कम है। वित्त वर्ष 2020 में भी नई पेशकशों की रफ्तार कमजोर थी और तुलनात्मक रूप से 35 लाख वर्ग फुट के मुकाबले सिर्फ 16 लाख वर्ग फुट की ही बिक्री दर्ज की गई। शोभा ने भी ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म की पेशकश की जिसमें वह बिक्री बढ़ाने के लिए कैशबैक भी मुहैया करा रही है। इसकी सफलता के आधार पर कंपनी इस योजना को आगे बढ़ा सकती है।

बाजार पर गोदरेज प्रॉपर्टीज के मजबूत परिचालन प्रदर्शन का असर दिख रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज का शेयर पिछले तीन कारोबारी सत्रों में बीएसई रियल्टी की 3.5 प्रतिशत की तेजी के मुकाबले 13 प्रतिशत तक मजबूत हुआ है।

गोदरेज प्रॉपर्टीज ने सोमवार को निवेशकों को दी जानकारी में कहा था, 'भले ही लॉकडाउन और उसके बाद पड़ने वाले प्रभाव की वजह से वित्त वर्ष 2021 की शुरुआत धीमी रह सकती है, लेकिन कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट और परियोजना ऑर्डर प्रवाह से उसे आने वाले महीनों में परिचालन रफ्तार बनाए रखने में मदद मिलेगी।'

भले ही प्रतिस्पर्धियों को संघर्ष से जूझना पड़ रहा है, लेकिन कंपनी ने अपनी शानदार तिमाही बिक्री दर्ज की है

गोल्डमैन सैक्स ने घटाया जीडीपी में बढ़त का अनुमान

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 8 अप्रैल

गोल्डमैन सैक्स को आशंका है कि साल 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाएगी और कोरोनावायरस महामारी के कारण वैश्विक जीडीपी की रफ्तार 2020 में शून्य से भी 1.8 फीसदी कम रहेगी। ताजा भविष्यवाणी इस साल की शुरुआत में जताए गए अनुमान में 5 फीसदी की गिरावट और 22 मार्च के अनुमान के मुकाबले करीब 3 फीसदी की कमी दर्शाती है।

वैश्विक रिसर्च हाउस ने भारत के लिए वास्तविक जीडीपी का अनुमान वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पहले के 3.3 फीसदी से घटाकर 1.6 फीसदी कर दिया है। यह हालांकि अभी भी अमेरिका से ज्यादा है, जो साल 2020 में -6.2 फीसदी रहने वाली है। हालांकि पहले इसके 3.7 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया था।

गोल्डमैन सैक्स के प्रमुख अर्थशास्त्री (एशिया प्रशांत) एंड्रयू टिल्टन ने प्राची मिश्रा के साथ लिखी एक रिपोर्ट में कहा है, हमें अनुमान है कि क्रमिक आधार पर वास्तविक जीडीपी बढ़त 2020 की पहली तिमाही में -1.4 फीसदी रहेगी जबकि दूसरी तिमाही में -3.8 फीसदी और तीसरी व चौथी तिमाही में क्रमशः 2 फीसदी और 7.5 फीसदी रहने का अनुमान है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में 11 फीसदी की मजबूती आएगी।

पहले चढ़ा फिर कोरोना के डर से टूटा बाजार

बीएस संवाददाता
मुंबई, 8 अप्रैल

भारतीय बाजारों में बुधवार को अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई और बेंचमार्क सूचकांकों ने एक दिन पहली 9 फीसदी की बढ़ोतरी में 4 फीसदी की उछाल और जोड़ दी। हालांकि तेजी की धार बाद में रह नहीं पाई क्योंकि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन में और बढ़ोतरी के डर ने निवेशकों की अवधारणा पर असर डाला। साथ ही यूरोपीय बाजारों की कमजोर शुरुआत और डॉलर के मुकाबले रुपये में भारी गिरावट का भी शेयर कीमतों पर असर पड़ा। 31,200 अंक तक चढ़ने के बाद सेंसेक्स 173.25 अंक यानी 0.58 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी 44 अंक फिसलकर 8,749 अंक पर बंद हुआ जबकि कारोबारी सत्र के दौरान यह 9,132 अंक की ऊंचाई को छू लिया था।

इंडेक्स की दिग्गज कंपनियां मसलन एचयूएल, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक अपने दिन के उच्चस्तर से तेजी से नीचे आए। विदेशी निवेशक लगातार दूसरे दिन शुद्ध खरीदार रहे। बुधवार को उन्होंने 1,943 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की, वहीं देशी निवेशकों ने 1,758 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। विदेशी निवेश के बावजूद डॉलर के मुकाबले रुपया 76.34 पर बंद हुआ, जो एक दिन पहले के बंद भाव 75.63 से करीब एक फीसदी नीचे है। एक दिन पहले भारतीय बाजारों ने 11 वर्ष की सबसे मजबूत एकदिवसीय बढ़ोतरी दर्ज की थी और यह बढ़ोतरी इस आशा में हुई थी कि यूरोप में कोरोनावायरस का प्रसार कम हो रहा है, जो नए वायरस हॉटस्पॉट के तौर पर उभरे थे।

बाजार का गणित लगातार दूसरे दिन मजबूत था और हर दो चढ़ने वाले शेयरों पर एक गिर रहा था। मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में करीब 2 फीसदी की उछाल दर्ज हुई।

कोटक सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख (डेरिवेटिव) सहज अग्रवाल ने कहा, संकेतकों से पता चलता है कि निफ्टी 9,300-9,400 तक जा सकता है। इंडेक्स का समर्थन स्तर 8,500-8,700 है। मौजूदा बढ़ोतरी का आधार व्यापक है और ऐसे में आगामी कारोबारी सत्रों में सकारात्मकता बनी रहने की उम्मीद है। हालांकि सेंसेक्स व निफ्टी में चढ़ने व गिरने वाले शेयरों की संख्या बराबर थी। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में लाभ वाले शेयर रहे सन फार्मा, एनटीपीसी और इंडसइंड बैंक और इनमें 4-4 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड 76 के करीब रुपया

डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर 76.38 पर बंद हुआ क्योंकि उभरते बाजारों की मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में मजबूती दर्ज हुई। रुपया एक दिन पहले के 75.64 प्रति डॉलर के मुकाबले करीब एक फीसदी नीचे बंद हुआ। एक करेंसी डीलर ने कहा, रुपये की गिरावट थामने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने हस्तक्षेप नहीं किया। बाजार में कारोबारी समय में कटौती ने भी विनिमय दर में अपनी भूमिका निभाई। ऐसे बाजार में हर छोटा प्रवाह या मांग विनिमय दर में काफी बदलाव कर सकता है।

आईएफए ग्लोबल ने एक नोट में कहा, वैश्विक स्तर पर कमजोर अवधारणा और मजबूत डॉलर ने रुपये पर असर डाला। साथ ही एफआईआई की स्थायी निकासी और नियामकीय हस्तक्षेप न होने से और कमजोरी देखने को मिली। आईएफए ग्लोबल ने कहा, रुपया अब एशियाई मुद्राओं में सबसे ज्यादा टूटी हुई मुद्राओं में शामिल है। दुनिया भर की अहम मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की माप करने वाला डॉलर इंडेक्स 0.10 फीसदी चढ़कर 100 पर पहुंच गया। विशेषज्ञों ने कहा कि आरबीआई उस समय रुपये को शायद ही संरक्षण दे सकता है जब आर्थिक गतिविधियां और निर्यात या आयात कोरोनावायरस के कारण करीब-करीब थम सा गया है। हालांकि यूबीएस के विशेषज्ञों ने कहा कि रुपया वापस 72-75 के स्तर पर लौट सकता है, जब कोरोनावायरस की स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। *बीएस*

आईपीओ में द्वितीयक बिक्री का वर्चस्व

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 8 अप्रैल

आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) बाजार में द्वितीयक बिक्री का वर्चस्व बना हुआ है और आईपीओ से मिलने वाली कुल रकम में ऐसी बिक्री की हिस्सेदारी लगातार तीसरे वित्त वर्ष (2020) में 80 फीसदी से ज्यादा रही। वास्तव में द्वितीयक शेयर बिक्री की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2015 के बाद से हर साल बढ़ी है और यह 41 फीसदी से बढ़कर वित्त वर्ष 2020 में 88 फीसदी पर पहुंच गई। द्वितीयक बिक्री की ज्यादा हिस्सेदारी को नकारात्मक नहीं माना जाता क्योंकि यह प्राइवेट इक्विटी को निकासी का मौका देता है, ऐसे में नई कंपनियों में निवेश के लिए रकम मुक्त हो जाती है। यह प्रवर्तकों को भी अपनी हिस्सेदारी का कुछ भाग बेचने में मदद करता है, ऐसे में वे सूचीबद्ध कराने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।

> द्वितीयक शेयर बिक्री की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2015 के बाद से हर साल बढ़ी है और यह 41 फीसदी से बढ़कर वित्त वर्ष 2020 में 88 फीसदी पर पहुंच गई

हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि आईपीओ बाजार की असंतुलित प्रकृति चिंता के संकेत हैं क्योंकि यहां द्वितीयक बिक्री का वर्चस्व बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि इसके परिणामस्वरूप इक्विटी के सिर्फ स्वामित्व का बदलाव होता है। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि विस्तार और नई विनिर्माण इकाइयां लगाने के लिए इक्विटी बाजारों का कम से कम इस्तेमाल करने का यह संकेत देता है।

बाजार के प्रतिभागियों ने कहा कि गहन पूंजी क्षेत्र वाली काफी कम कंपनियां बाजार में उतर रही हैं। आईआईएफएल सिक्योरिटीज के प्रमुख (निवेश बैंकिंग) निपुण गोयल ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में बड़े इश्यू बीमा व वित्तीय कंपनियों ने पेश किए, जो अच्छी तरह से पूंजीकृत थीं और उन्हें अनिवार्य रूप से प्राथमिक पूंजी की दरकार नहीं थी। किसी आईपीओ में प्राथमिक व द्वितीयक बिक्री का मिश्रण कंपनी की फंडिंग की जरूरत के बारे में बताता है और यह भी कि क्या मौजूदा निवेशक मुद्रीकरण करना चाहते हैं या नहीं। सार्वजनिक बाजार के निवेशक चाहेंगे कि जिस कंपनी में वे निवेश कर रहे हैं वह अच्छी तरह से पूंजीकृत है। अगर आप कंपनी की जरूरत से ज्यादा प्राथमिक बिक्री से रकम जुटाते हैं तो यह इक्विटी पर रिटर्न को हतोत्साहित करेगा।

विशेषज्ञों ने कहा कि भारतीय बाजार उन इकाइयों के लिए प्रतिकूल हो गया है जिन्हें अपने कारोबार को बनाए रखने के लिए ज्यादा पूंजी की दरकार है। ऐसे में रियल एस्टेट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, बिजली और बड़े पैमाने पर विनिर्माण वाले क्षेत्र कई साल से शायद ही इक्विटी पूंजी बाजार से रकम जुटाने में सक्षम हो पाए हैं। पूंजी बाजार के स्वतंत्र प्रोफेशनल प्रांजल श्रीवास्तव ने कहा, यह प्रवृत्ति कंपनियों की प्रकृति को रेखांकित करता है, जिन्हें बाजार हाथोंहाथ लेगा। एक दशक पहले इन्फ्रा क्षेत्र की कंपनियां सूचीबद्ध हो जाती थी, जो परिसंपत्ति के मामले में समृद्ध होती थीं और उन्हें रकम की दरकार होती थी। जैसी कि चीजें नजर आ रही हैं, अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं हो रहा है। ऐसे में चक्र के पलटने तक यह प्रवृत्ति बनी रह सकती है।

विशेषज्ञों ने कहा कि पसंदीदा फर्म बनने के लिए इन्फ्रा व विनिर्माण कंपनियों को सबसे पहले अपनी वित्तीय स्थिति सुधारनी होंगी।

उद्योग जगत ने मांगा 23 लाख करोड़ रुपये का पैकेज

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 8 अप्रैल

उद्योग जगत ने देशबंदी को धीरे-धीरे खत्म किए जाने और उद्योग व समाज के कमजोर तबके के लिए 23 लाख करोड़ रुपये तक का पैकेज दिए जाने की मांग की है।

एसोचेम ने 15 से 23 लाख करोड़ रुपये (200 बिलियन से 300 बिलियन डॉलर), फिक्की ने 9 से 10 लाख करोड़ रुपये, पीएचडीसीसीआई ने 9 लाख करोड़ रुपये और सीआईआई ने जीडीपी के 2 प्रतिशत के बराबर पैकेज दिए जाने की जरूरत बताई है। अगर देश की अर्थव्यवस्था का आकार वित्त वर्ष 21 में 224.89 लाख करोड़ रुपये माना जाए, जिसके आधार पर बजट तैयार किया गया है तो जीडीपी का 2 प्रतिशत 4.5 लाख करोड़ रुपये होता है। बहरहाल अर्थव्यवस्था का आकार इस परिकल्पना की तुलना में बहुत कम हो सकता है।

भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष के मुताबिक उद्योगों को बढ़ने में मदद करने व श्रमिकों को भुगतान करने व राज्यों को बजट समर्थन देने के लिए 6.6 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी। उन्होंने देशबंदी को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की भी बात की।

सीआईआई की ओर से वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों को भेजे गए एक नोट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी वृद्धि दर दो प्रतिशत से ज्यादा रहने की संभावना नहीं है, वृद्धि दर इससे कम भी रह सकती है। चैंबर ने कहा है, 'यह हमारा सुविचारित फैसला है कि इसका असर बहुत बुरा होगा। हम सरकार के इस विचार से पूरी तरह से सहमत हैं कि जितनी जल्दी हो सके, बंदी को धीरे धीरे हटाने की जरूरत है।'

सीआईआई ने कहा है कि सरकार को एक डैशबोर्ड तैयार करने की जरूरत है, जिस पर इस महामारी के बारे में विभिन्न प्रमुख शहरों और राज्यों से संबंधित जानकारी दी गई हो। शहरों व राज्यों में काम शुरू करना इस डैशबोर्ड पर आधारित होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि धीरे-धीरे छूट दिए जाने से मानव संसाधन के निश्चित अनुपात में काम पर वापस लौटेगा और डैशबोर्ड पर हो रहे बदलाव के आधार पर उनकी आवाजाही तय की जानी चाहिए।

जिन क्षेत्रों में घर से काम करना मुश्किल है और वे बड़े पैमाने पर रोजगार देते हैं, उन्हें सबसे पहले शुरू किए जाने की जरूरत है।

पहले चरण में विनिर्माण, ई-कॉमर्स और निर्माण हो सकते हैं। इसके साथ ही लॉजिस्टिक्स और परिवहन को परिचालन की अनुमति दूसरे चरण में दी जानी चाहिए, जो पहले चरण के दो से तीन सप्ताह बाद हो सकता है। चैंबर ने कहा है कि अन्य शेष क्षेत्रों में काम डैशबोर्ड पर होने वाली प्रगति के आधार पर शुरू किया जाना चाहिए।

काम शुरू करने के बाद 50 प्रतिशत कर्मचारियों को बहाल करने में करीब 3 सप्ताह लग सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे इसे बढ़ाया जा सकता है, जो इस पर आधारित हो कि विभिन्न शहरों व राज्यों में डैशबोर्ड में बदलाव की क्या स्थिति है। जीडीपी के 2 प्रतिशत पैकेज की मांग का औचित्य बताते हुए चैंबर ने कहा है कि संकट जल्द खत्म नहीं होने जा रहा है, सरकार को अपनी सभी ताकत अचानक लगा देने की जरूरत नहीं है।

रियल एस्टेट क्षेत्र की समस्या तेजी से बैंकिंग व वित्तीय क्षेत्र तक पहुंच जाने के डर को देखते हुए चैंबर चाहता है कि सरकार 30,000 करोड़ रुपये के एक कोष का गठन करे, जिसका इस्तेमाल बैंक कुछ दारयों और कुछ विशेष शर्तों के साथ कर सकें। बैंक इस धन का इस्तेमाल टियर-1 बॉन्ड जारी करने के माध्यम से कर सकते हैं, जो फंड के विकल्प के माध्यम से इक्विटी में बदल सकेगा। चैंबर ने समाज के हाशिये पर रहने वाले लोगों के लिए अतिरिक्त समर्थन देने की मांग की है, जो सरकार द्वारा हाल में घोषित 1.7 लाख करोड़ रुपये पैकेज से अतिरिक्त होगा। इसमें जेएएम खाताधारकों को 2 लाख करोड़ रुपये दिए जाने की मांग की गई है।

इसमें सरकार को उद्योग के लिए सीधे सब्सिडी देने के बजाय, जैसा कि

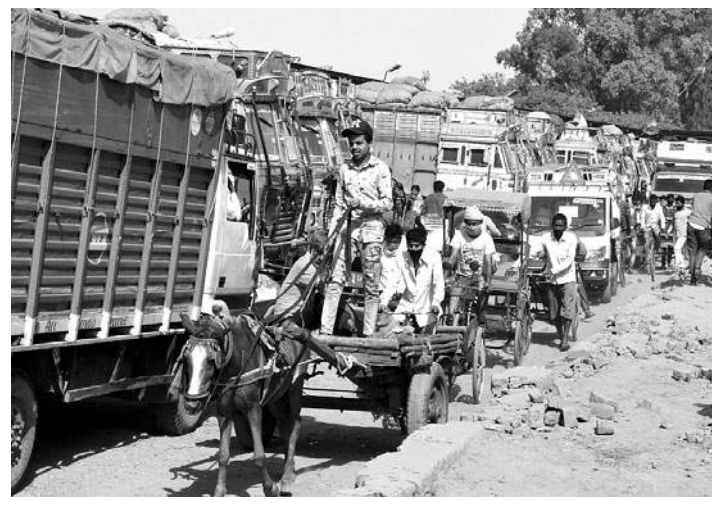

कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए की गई देशबंदी में आवश्यक वस्तुओं के अलावा सभी कारोबारी गतिविधियां ठप पड़ गई हैं। बुधवार को दिल्ली की आजादपुर मंडी का दृश्य। बुधवार से आजादपुर मंडी में एक ट्रक - एक कारोबारी का नियम लागू किया गया है और अगर कारोबारी इसका पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी *फोटो-पीटीआई*

देशबंदी का धीरे-धीरे खात्मा चाहता है उद्योग

- एसोचेम ने 15 से 23 लाख करोड़ रुपये, फिक्की ने 9 से 10 लाख करोड़ रुपये, पीएचडीसीसीआई ने 9 लाख करोड़ रुपये और सीआईआई ने जीडीपी के 2 प्रतिशत के बराबर पैकेज दिए जाने की जरूरत बताई
- बैंकों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी मुहैया कराने की जरूरत है, जो उधारी लेने वाले के अप्रैल-जून के वेतन बिल के बराबर हो
- कोविड बीमा योजना की घोषणा विस्थापित श्रमिकों के लिए भी 3 महीने के लिए होनी चाहिए
- उद्यमों को सीधे धन के बजाय कर्ज में लीवरेज बढ़ाया जाए

अन्य तमाम देशों में किया गया है, बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से लीवरेज (5-6 गुना) देने और उद्योग को बैंकों के माध्यम से समर्थन दिए जाने की मांग की गई है।

इसमें कहा गया है, 'हमारा अनुमान है कि अर्थव्यवस्था को 14-14 प्रतिशत कर्ज विस्तार दिए जाने की जरूरत है।' इसमें मांग की गई है कि बैंकों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी मुहैया कराने की जरूरत है, जो उधारी लेने वाले के अप्रैल-जून के वेतन बिल के बराबर हो और इसको सरकार की ओर से गारंटी मिले और रिजर्व बैंक की रिफाइनैंस गारंटी के साथ उस पर 4 से 5 प्रतिशत ब्याज लिया जाए। चैंबर ने कहा है कि अप्रैल-जून की ब्याज बाध्यता को लेकर इसी तरह की सुविधा दबाव वाले क्षेत्रों को भी दी जानी चाहिए। चैंबर यह भी चाहता है कि बैंकों को कार्यशील पूंजी को लेकर सभी उद्योगों के लिए बढ़ी कर्ज सीमा तय करने की अनुमति दी जाए। सीआईआई ने कहा है कि कोविड बीमा योजना की घोषणा विस्थापित श्रमिकों के लिए भी 3 महीने के लिए होनी चाहिए, जिसपर आने वाले खर्च का एक हिस्सा उद्योग और एक हिस्सा सरकार वहन करे। उसके बाद विस्थापित कर्मचारियों को स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा ई पास जारी किए जाने चाहिए, जिससे वे अपने कार्यस्थल तक पहुंच सकें।

फिक्की ने कहा है कि अर्थव्यवस्था के सभी स्तरों पर राहत और पुनर्वास के लिए 9 से 10 लाख करोड़ रुपये डाले जाने की जरूरत है, जिसमें निचले स्तर से लेकर पिरामिड के उपरी स्तर तक के लोग यानी अनौपचारिक श्रमिकों, एमएसएमई और बड़े कॉर्पोरेट तक शामिल हों। चैंबर चाहता है कि कोविड के बाद के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का पुनरुद्धार कोष 'भारत सेल्फ सफिसिएंसी फंड' बनाया जाना चाहिए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे गए पत्र में एसोचेम ने कहा है कि अगले 12 से 18 महीने में भारत की अर्थव्यवस्था में 200 अरब डॉलर डालने की जरूरत है, जो 300 बिलियन डॉलर तक हो सकता है। इसमें कहा गया है कि अगले 3 महीने में व्यवस्था में 50 से 100 अरब डॉलर (3.8 से 7.6 लाख करोड़ रुपये) नकदी डाले जाने की जरूरत है, जिससे नौकरियां जाने के नुकसान को रोका जा सके।

पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष डीके अग्रवाल ने कहा, 'सरकार ने पहले ही 2 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज दिया है। हमें उम्मीद है कि भारत के कारोबार व उद्योग के लाभ और विभिन्न राहत कदमों के तहत सरकार शेष 9 लाख करोड़ रुपये का पैकेज और जारी करेगी।'

सरकार के लिए आसान नहीं सस्ती उधारी

अनूप रॉय
मुंबई, 8 अप्रैल

सरकार गुरुवार को इस वित्त वर्ष में रुपये जुटाने के लिए 19,000 करोड़ रुपये की नीलामी आयोजित करेगी। हालांकि वर्तमान दौर में सरकार लिए सस्ते कर्ज की संभावना लुप्त होती जा रही हैं।

बुधवार की नीलामी में बॉन्ड डीलरों ने राज्य सरकारों से दरों में बढ़ोतरी करने के लिए कहा है। राज्यों ने बाजार से पैसा उठाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को 150-200 आधार अंकों की बढ़त तथा नीतिगत रीपो दर को 400 आधार अंकों की बढ़त पर उधार लिया। एएए रेटिंग वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई आरईसी ने 5,000 करोड़ रुपये की ऋण बिक्री की योजना को वापस ले लिया। केरल ने 15 साल के बॉन्ड के लिए 8.96 फीसदी का भुगतान किया। समान समयावधि पर परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियां 6.92 प्रतिशत पर बंद हुई।

दिलचस्प पहलू यह है कि तरलता बढ़ाने के दूसरे नीतिगत उपायों के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा नीतिगत दरों में 75 आधार अंकों की कटौती के बावजूद बांड यील्ड

में तेजी आई है, जो केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य तरलता बढ़ाने के उपायों के साथ थी। पहले, 10 साल की बॉन्ड यील्ड 6 फीसदी तक आ गई थी, लेकिन बुधवार को यह 6.44 प्रतिशत पर रही। इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में सरकार को 4.88 लाख करोड़ रुपये की उधारी लेनी है लेकिन कोरोनावायरस के चलते इन लक्ष्यों को पूरा करने में मुश्किलें आ रही हैं।

बॉन्ड डीलरों का कहना है कि यील्ड वर्तमान स्तर के आसपास रहेगी, लेकिन वे बॉन्ड जारी करने से इनकार नहीं करेंगे। सरकार ने अभी तक अतिरिक्त उधारी को लेकर संपर्क नहीं किया है। बाजार में यह चर्चा है कि अगर सरकार ऐसा करती है तो वह सीधे आरबीआई से संपर्क कर सकती है। फिलिप कैपिटल में फिक्स्ड इनकम के लिए कंसल्टेंट जयदीप सेन ने कहा, 'बाजार सरकारी प्रतिभूतियों की ऊंची कीमतों पर दांव लगा रहा है। आरबीआई द्वारा दरों में कटौती तथा तरलता संबंधी प्रावधानों के बाद भी सरकारी प्रतिभूतियां लगभग स्थिर हैं। राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का उल्लंघन होगा लेकिन अभी इसे वापिस पाने के लिए समय शेष होगा। यग इस बात पर भी निर्भर करेगा कि लोग कितनी जल्दी काम पर लौटते हैं।'

बॉन्ड मार्केट क्षेत्र से जुड़े कुछ विशेषज्ञ आरबीआई से उम्मीद करते हैं कि वह सेकंडरी मार्केट से बॉन्ड खरीदने के लिए खुले बाजार की प्रक्रियाओं (ओएमओ) की घोषणा करेगा, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि यह माहौल को अधिक प्रभावित नहीं कर सकेगा।

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के एसोसिएट पार्टनर सौम्यजीत नियोगी ने कहा, 'दस वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियां पहले से ही रीपो दर से 200 आधार अंक ऊपर है। यह एक असामान्य समय हैं। कयासबाजी, अटकलों, संभावित वित्तीय फिसलन पर स्पष्टता की कमी ... बहुत से ऐसे कारक हैं जिससे बाजार परेशान हो रहा है। स्पष्टता बहुत जरूरी है।'

वेतन के लिए धन मिलने की आस नहीं

सोमेश झा
नई दिल्ली, 8 अप्रैल

राजकोषीय गुंजाइश के अभाव के कारण सरकार उद्योगों को कोविड-19 महामारी के कारण काम नहीं कर पा रहे कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए अनुदान की घोषणा नहीं कर पाएगी। इस मामले के जानकार कई सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है।

सूत्रों ने कहा कि पिछले कई दिनों में उद्योग के प्रतिनिधियों ने शीर्ष सरकारी अधिकारियों से मुलाकात कर एक आर्थिक पैकेज पर चर्चा की है जिस पर फिलहाल काम चल रहा है।

बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत करने वाले दो में से एक व्यक्ति ने कहा, 'सरकार के पास राजकोषीय गुंजाइश का अभाव है। उद्योग के मजदूरी बिलों के मद्देनजर उन्हें अनुदान देना मुमकिन नहीं होगा।'

सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती की अगुआई में अधिकारियों का एक अधिकार प्राप्त समूह बनाया है जिसे आर्थिक और कल्याण उपायों पर सिफारिशों को अंतिम रूप देना है।

सूत्रों के मुताबिक समिति ने उद्योग से इनपुट लिए हैं।

दूसरे व्यक्ति ने कहा, 'आर्थिक वृद्धि बुरी तरह से प्रभावित होने और सभी स्रोतों से राजस्व में कमी आने से राजकोषीय स्थिति ठीक नहीं है। राज्यों का भी राजकोषीय घाटा काफी बढ़ गया है। भारत रेटिंग एजेंसियों की ओर से रेटिंग में कमी किए जाने का भार वहन नहीं कर सकता क्योंकि इससे निवेश के परिदृश?यपर असर होगा। ऐसे माहौल में वेतन बिल को सहायता दे पाना मुश्किल लग रहा है।'

वैश्विक महामारी
कोरोनावायरस

वित्त वर्ष 2020 के लिए केंद्र का राजकोषीय घाटा पहले ही संशोधित अनुमान से ऊपर जा चुका है। संशोधित अनुमान में इसे जीडीपी का 3.8 फीसदी किया गया था जबकि इसका बजट अनुमान 3.3 फीसदी था। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने घाटा जीडीपी के 3.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है जबकि राजकोषीय समेकन के रोडमैप में इसे 3 फीसदी पर रहने का अनुमान जताया गया था। इस तरह से सरकार वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 दोनों वित्त वर्ष के लिए 0.5 प्रतिशत अंकों का मोचन फंड ले चुकी है।

स्टैंडर्ड ऐंड पूअर्स और फिच द्वारा देश की सॉवरिन रेटिंग न्यूनतम निवेश स्तर पर है। मूडीज ने भारत को न्यूनतम निवेश स्तर से एक निशान ऊपर रखा है।

समिति ने उद्योग के साथ अनौपचारिक चर्चा की है जिसमें सूक्ष्म उद्यमों को दो महीनों के लिए अनुदान देने और बाकी बची छोटी कंपनियों के लिए ऋण मॉडल के आधार पर अनुदान देने का प्रस्ताव है।

कुछ देशों ने अर्थव्यवस्था में नौकरियां खत्म होने से रोकने के लिए अनुदान के जरिये वेतन बिल का भुगतान करने की घोषणा की है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन ने कारोबारियों के लिए 350 अरब यूरो के एक राहत पैकेज का ऐलान किया जिसके तहत वहां की सरकार हर महीने 2,500 यूरो तक कमाने वाले कर्मचारियों के 80 फीसदी तक के वेतन का भुगतान करेगी।

कृषि क्षेत्र को देशबंदी से छूट मिलने के बावजूद बनी हुई हैं मुश्किलें

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 8 अप्रैल

कुछ साल पहले किसानों के विरोध प्रदर्शन का केंद्र रहे मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ गांव के सीमांत किसान जगन्नाथ को इन दिनों अजीब समस्या से जूझना पड़ रहा है। कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए 21 दिन की देशबंदी की घोषणा की गई है और पुलिस की जांच संबंधी गतिविधियां बढ़ गई हैं। जगन्नाथ का कहना है, 'सरकार ने कृषि और मड़ाई संबंधी काम को देशबंदी से छूट दी है, लेकिन हमें बाहर निकलते समय स्थानीय सिपाही से हर समय जूझना पड़ता है और कुछ भी नहीं हो पा रहा है।'

देश की प्रमुख कृषि उपकरण विनिर्माता एस्कॉर्ट्स एग्री मशीनरी के मुख्य कार्याधिकारी शेनू अग्रवाल कहते हैं कि उनकी फर्म के कर्मचारी व डीलर भी इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा, 'केंद्र व प्रमुख राज्य सरकारों ने आदेश जारी कर कृषि उपकरणों और उनकी मरम्मत की दुकानों और खुदरा कारोबारियों को देशबंदी से छूट को लेकर आदेश जारी किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर तमाम चुनौतियां बनी हुई हैं। हमारे डीलरों को जिलाधिकारियों से कर्फ्यू पास ले पाना बड़ी समस्या है।'

उन्होंने कहा कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फसल कटाई हो रही है, जबकि कृषि मशीनरी की मरम्मत और खुदरा दुकानें बहुत जरूरी हैं, जिससे फसल काटने का काम आसानी से चल सके।

देश में संगठित क्षेत्र के करीब 10,000 कृषि उपकरण की खुदरा और विनिर्माण से जुड़े प्रतिष्ठान हैं, जबकि हजारों की संख्या असंठित क्षेत्र के कारोबारी हैं। पिछले सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कृषि मशीनरी रिपेयर और रिटेल दुकानों को देशबंदी से छूट दी थी। अटकलें लगाई जा रही हैं कि देशबंदी की अवधि बढ़ सकती है, ऐसे में पिछले कुछ दिनों के दौरान मिली छूट को लेकर स्पष्टीकरण देने और उनके बारे में जमीनी स्तर तक संदेश पहुंचाने की जरूरत है, जिससे स्थानीय अधिकारी उस पर अमल करें और खेती बाड़ी संबंधी काम सरल करें, जिससे इस पर प्रभाव न पड़ने पाए।

एस्कॉर्ट्स ने अपने स्तर पर 10 वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाई है, जो रोजाना विभिन्न राज्यों के जिले के अधिकारियों से संपर्क में रहते हैं, जिससे दुकानों को कर्फ्यू पास और काम करने संबंधी जरूरी अनुमति मिल सके। अग्रवाल ने कहा, 'उत्तर प्रदेश ने कर्फ्यू पास और अनुमति के लिए केंद्रीकृत आवेदन की अनूठी व्यवस्था की है। वहीं अन्य राज्यों में डीलरों को या हमारी टीम के सदस्यों को स्थानीय प्राधिकारियों के संपर्क में रहना पड़ता है और नजर रखनी पड़ती है कि ट्रैक्टर दुकानदारों या कर्मचारियों का पुलिसिया उत्पीड़न न हो।' बड़ी एनिमल फीड विनिर्माता अनमोल फीड्स के प्रबंध निदेशक अमित सरावगी ने कहा कि अलग अलग राज्यों द्वारा कानून की अलग अलग व्याख्या एक और समस्या है। सरावगी कहते हैं कि जमीनी स्तर पर छूट के बारे में सूचना न होने की वजह से मछलियों, जानवरों व पक्षियों का चारा लाने और ले जाने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा, 'मछलियों के चारे को आवश्यक जिंस में रखा गया है और इसे देशबंदी से छूट मिली हुई है। लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने इसे अलग से अधिसूचित नहीं किया है, जिसकी वजह से फिश फीड ले जा रही हमारी एक ट्रक को कुछ दिन पहले असम सीमा पर रोक दिया गया।' उन्होंने कहा कि आदमी भले ही बगैर खाए कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन पशुओं को बगैर चारे के 4 घंटे रखना भी मुश्किल है।

किसान नेताओं का भी कहना है कि फसल से जुड़े बड़े उपकरणों जैसे थ्रेसर और हार्वेस्टर की आवाजाही की अनुमति है, लेकिन राज्य की सीमा पार करते समय उनकी जांच होती है, जिससे

आवाजाही में देरी हो रही है।

भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चदूनी ने कहा, 'अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरी जानकारी में बीज, खाद बेचने वाली 40 प्रतिशत दुकानें बंद हैं। कृषि उपकरणों की दुकानें खुली हैं, लेकिन छूट के बावजूद ज्यादातर दुकानें बंद हैं।' उन्होंने कहा कि अगर किसी को ट्रैक्टर के पुर्जे शहर से लाने हों तो उन्हें 10 जगह रोका जाता है। उन्होंने कहा, 'ऐसी स्थिति का सामना कितने किसान कर सकते हैं।' उन्होंने कहा कि हार्वेस्टरों व थ्रेसरों की आवाजाही भी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हरियाणा में गेहूं की मड़ाई प्रभावित हो रही है, जो राज्य की मुख्य फसल है।

कृषि क्षेत्र को देशबंदी से मुक्त किए जाने के बावजूद किसानों को समस्याएं हो रही हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हुई 21 दिन की देशबंदी के दौरान बुधवार को पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में खेत से गाजर निकालते कामगार *फोटो-पीटीआई*

राज्यों को 14,103 करोड़ रुपये जीएसटी मुआवजा जारी

वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के तहत उन्हें करीब 34,000 करोड़ रुपये दो चरणों में जारी किया है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में राज्यों को राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए यह राशि दी गई है। इसमें से 14,130 करोड़ रुपये मंगलवार को जारी किए गए।

सूत्रों ने बताया कि इस ताजा भुगतान के साथ वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर और नवंबर के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति मद में करीब 34,000 करोड़ रुपये लंबित बकाया का भुगतान कर दिया है। सूत्रों के अनुसार पहली किस्त में 19,950 करोड़ रुपये 17 फरवरी को जबकि शेष राशि 14,103 करोड़ रुपये राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को मंगलवार को जारी की गई। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय दिसंबर और जनवरी के लंबित बकाए के भुगतान पर भी गौर कर रहा है और इसे चरणबद्ध तरीकेसे जल्द जारी किया जा सकता है। *भाषा*

बीएस सूडोकू 3710

परिणाम संख्या 3609

	3				9		6	
		5						
						8		
5				7				
		8		4			9	
7	2	1			5		3	
			7					
6								
				8	2	4		7

6	1	8	2	7	4	3	5	9
5	2	9	6	3	8	4	7	1
3	4	7	5	9	1	8	6	2
9	7	3	8	5	2	1	4	6
2	6	5	4	1	3	7	9	8
1	8	4	9	6	7	5	2	3
7	3	6	1	2	5	9	8	4
8	5	2	3	4	9	6	1	7
4	9	1	7	8	6	2	3	5

कैसे खेलें? बहुत आसान

हर, रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बंदी में मोटर बीमा क्षेत्र से बीमा के दावों में कमी

सुब्रत पांडा
मुंबई, 8 अप्रैल

गैर जीवन बीमा क्षेत्र में इस समय स्वास्थ्य क्षेत्र में दावे बढ़े हैं, लेकिन मोटर क्षेत्र में खुद की क्षति के दावे कम हो गए हैं। देशबंदी के दौरान बहुत कम वाहन सड़क पर हैं। इसकी वजह से दुर्घटनाएं कम हो रही हैं और दावे कम आ रहे हैं। कम दावे आने से बीमाकर्ताओं के नुकसान अनुपात सुधरने की संभावना है, लेकिन इसे लेकर उद्योग की अलग-अलग राय है।

नुकसान अनुपात से बीमाकर्ता के प्रदर्शन का संकेत मिलता है। अगर यह 100 प्रतिशत से ज्यादा होगा तो एकत्र किया गया प्रीमियम दावे के भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इस समय मोटर क्षेत्र में उद्योग का नुकसान अनुपात 80 प्रतिशत है।

पॉलिसीबाजार डॉट कॉम के मोटर बिजनेस के प्रमुख सज्जा प्रवीण चौधरी ने कहा, 'हमारे पास एक से डेढ़ महीने हैं, जब दुर्घटनाएं नहीं होंगी। इससे नुकसान अनुपात पर 10 प्रतिशत असर होगा।' बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के खुदरा दावों के प्रमुख संजय सक्सेना ने का भी कहना है कि नुकसान कम होगा, क्योंकि इस दौरान दावे कम आएंगे।

- कुछ बीमाकर्ताओं का कहना है कि इससे कंपनियों का नुकसान अनुपात घटेगा
- वहीं कुछ अन्य का कहना है कि लॉकडाउन खुलने के बाद अचानक दावे बढ़ेंगे क्योंकि लंबित दावे आएंगे
- बीमा कंपनियों को अप्रैल से मरम्मत की लागत, कल पुर्जों के दाम और श्रम लागत बढ़ने की भी चिंता

वहीं दूसरी ओर कुछ का मानना है कि लॉकडाउन के बाद दावे बढ़ेंगे। इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुब्रत मंडल ने कहा, 'असली तस्वीर देशबंदी खुलने के बाद ही सामने आएगी। पिछले दावों के बढ़ने की संभावना है। यह संभव है कि पॉलिसीधारक इस समय यह सोचकर दावे न कर पा रहा हो कि इस समय वर्कशॉप नहीं चल रही है।'

एक निजी बीमा कंपनी के अधिकारी ने कहा, 'नुकसान अनुपात दुर्घटना और मरम्मत की लागत, श्रम लागत और कल पुर्जों की लागत पर निर्भर होता है। ज्यादातर विनिर्माता अप्रैल से इसमें बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। बीमा उद्योग ने पिछले 6 महीने में दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, न ही थर्ड पार्टी की दर बढ़ी है। ऐसे में नुकसान अनुपात घटने के बजाय बढ़ सकता है।'

आईसीआईसीआई लोंबार्ड के अंतरराइटिंग और क्लेम के प्रमुख संजय दत्त ने कहा, 'मोटर सेग्मेंट में नुकसान अनुपात कितना रहेगा, यह देशबंदी की अवधि पर निर्भर होगा। मोटर क्षेत्र में थर्ड पार्टी दावे तत्काल नहीं आते। थर्ड पार्टी दावे कम होते हैं या नहीं, यह भविष्य में पता चल सकेगा।' आर्थिक मंदी की वजह से मोटर बीमा क्षेत्र पिछले एक साल से मंदी के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि नए वाहनों की मांग कम है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 42

आगे आएं बहुराष्ट्रीय संस्थान

विश्व बैंक समूह जिसमें बैंक के अलावा निजी क्षेत्र पर केंद्रित इंटरनैशनल फाइनैंस कॉर्पोरेशन (आईएफसी) और ऋण गारंटी पर केंद्रित मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी (एमआईजीए) शामिल हैं, ने अब नोवेल कोरोनावायरस के कारण बढ़ते स्वास्थ्य और आर्थिक संकट को हल करने की दिशा में पहल की है। शुरुआत में इसके लिए 1.9 अरब डॉलर की राशि खर्च करने की मंजूरी दी गई थी जिसे 25 देशों में खर्च किया जाना है। बहरहाल इस राशि का बड़ा हिस्सा भारत में व्यय किया जाएगा और उसे इसमें से एक अरब डॉलर की राशि मिलेगी। इस पूंजी का आगमन अच्छी बात है और यह इस बात का संकेत भी है कि बैंक अपने मूल उद्देश्य पर काम कर रहा है। जो राशि भारत में कोविड-19 से निपटने के प्रयास में व्यय की जानी है वह देश की वित्तीय तंगी को परिलक्षित नहीं करती। हालांकि वित्तीय तंगी भी कम नहीं है। सच तो यह है कि बैंक के पैसे को जन स्वास्थ्य से जुड़ी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने में खर्च किया जा सकता है। समूह ने पहले ही यह संकेत दिया है कि संकट से जूझने के क्रम में उसे अंतिम तौर पर 160 अरब डॉलर की राशि व्यय करनी पड़ सकती है। आईएफसी के बारे में जानकारी है कि वह निजी क्षेत्र की सहायता और वैश्विक आपूर्ति शृंखला को बरकरार रखने के लिए 8 अरब डॉलर की पूंजी दे रहा है और एमआईजीए को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि दुनिया भर के विकासशील देशों की सरकारों की पहुंच पूंजी बाजार तक बनी रहे और उन्हें जीवन रक्षक उपकरण और दवाएं खरीदने में दिक्कत न हो।

यह अहम है कि विश्व बैंक समूह द्वारा दी जाने वाली राशि उन जगहों पर व्यय हो जहां इससे बड़ा अंतर पैदा होगा, बजाय कि उसे भारत जैसे देशों में अनुपूरक राज्य संसाधनों में व्यय करने में। उदाहरण के लिए विश्व बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुनिया भर का निजी क्षेत्र सुरक्षित महसूस करे और वेंटिलेटर तथा व्यक्तिगत संरक्षण उपकरणों यानी पीपीई जैसी अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन बाधित न हो। ऐसे में बैंक को खासतौर पर यह ध्यान देना चाहिए कि उक्त राशि उन उत्पादकों को सुरक्षा मुहैया कराए जो उत्पादन की लाइन बदलकर इन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहते हैं। पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद पानगड़िया कह चुके हैं कि इसके लिए खरीद गारंटी या खुली खरीद की पेशकश की जा सकती है।

आखिर दूसरे विश्वयुद्ध के बाद विश्व बैंक की स्थापना यूरोप की बाजार अर्थव्यवस्था दोबारा खड़ी करने के लिए की गई थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली महामारी को विश्वयुद्ध जैसा नहीं माना जा सकता है लेकिन इस दौरान उन बाजार संस्थानों की व्यापक सहायता आवश्यक है जो उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं और अर्थव्यवस्था की सेहत सुधार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल विश्व बैंक को आगे आना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय तंत्र के बचाव में आगे आना चाहिए। उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न देश इस संकट में मजबूत बने रहें। यह उसकी परीक्षा की घड़ी है क्योंकि संकट 2008 के वित्तीय संकट से काफी बुरा है। आईएमएफ ने कहा है कि करीब 90 देश उससे सहायता मांग चुके हैं। संकट के दौर से निपटने के लिए उसे हरसंभव वित्तीय मदद देनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि वित्तीय संकट के कारण सरकारों और कंपनियों पर दिवालिया होने का संकट नहीं मंडराना चाहिए। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि गहरे कर्ज में डूबे देश अपने सरकारी संसाधनों को स्वास्थ्य क्षेत्र में लगाने पर मजबूत होंगे। वे समय पर भुगतान नहीं कर पाएंगे। ऐसे में व्यापक ऋण माफी पर तत्काल विचार किया जाना चाहिए।

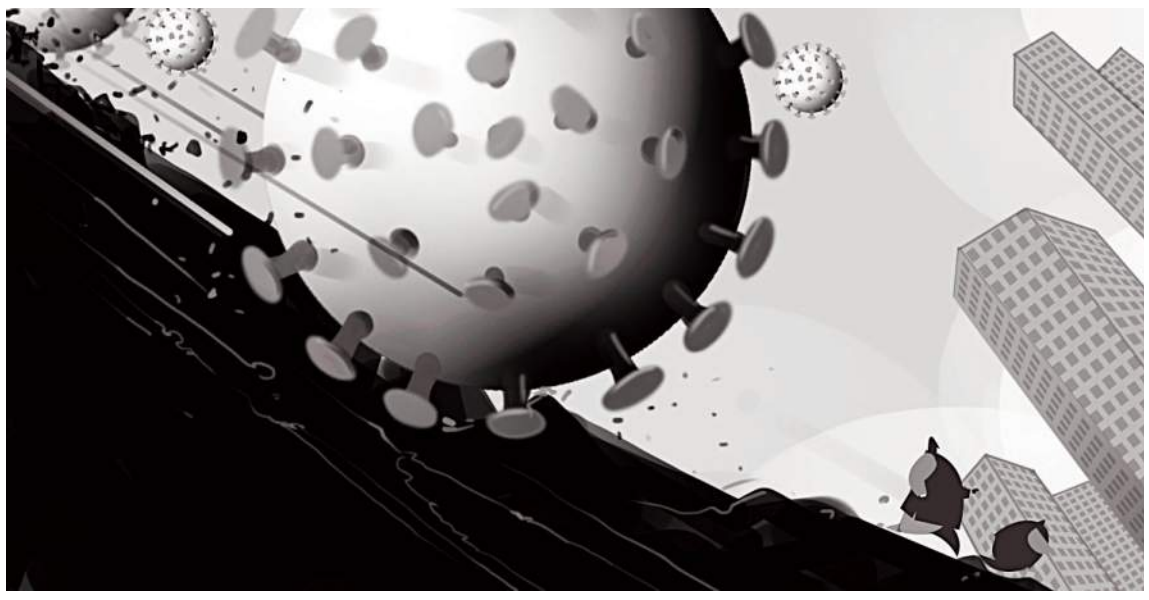

अजय मोहंती

कोविड-19 के द्वितीयक प्रभाव अधिक कष्टकारी

लॉकडाउन के दौरान कोरोनावायरस का प्रसार धीमा किया जा सकता है लेकिन इस घटना के आर्थिक दुष्प्रभावों का अंदाजा लगा पाना भी अभी मुश्किल लग रहा है। बता रहे हैं **देवाशिष बसु**

देश भर में 21 दिनों की पूर्ण बंदी (लॉकडाउन) जारी रहने के बीच मुझे ऐसा लगता है कि हम इस खुशनुमा उम्मीद में जी रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि खत्म होने के बाद हम कोरोनावायरस के प्रसार को नाटकीय रूप से धीमा कर पाएंगे और लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही हालात फिर से पटरी पर लौट आएंगे। यह खुशनुमा परिदृश्य अमेरिका और भारत जैसी कई अर्थव्यवस्थाओं में महामारी से उपजे दुष्प्रभावों को कम करने के लिए घोषित राहत पैकेजों के साथ मिलकर व्यापक स्तर पर होने वाले वैश्विक गतिरोध को कम कर सकेंगे। बाजारों को भी कुछ ऐसी ही उम्मीदें हैं और राहत पैकेज की घोषणा के बाद शेयर बाजारों में आई तेजी इसकी बानगी है। वैश्विक स्तर पर बाजारों में तेजी का रुख इसी उम्मीद और भरोसे पर टिका हुआ है।

लेकिन अगर यह विश्वास गलत साबित है तो क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जिस तरह इस महामारी के आगमन को लेकर उसे कमतर आंका, कहीं हम वैसे ही इससे उबरने में लगने वाले वक्त को कम आंक रहे हैं? मानव जाति बुनियादी तौर पर आशावादी होती है, यह एक ऐसा गुण है जो हमें अपनी सामान्य जिंदगी में काफी मदद करता है। मुश्किल वक्त में हम इसी गुण के सहारे फिर से खड़े होते हैं। हालांकि ऐसा वक्त भी होता है जब संशयग्रस्त होना भी एक गुण होता है और आशावाद का दामन पकड़े रहना सिर्फ बेवकूफी होती है। किसी महामारी की स्थिति में भी ऐसा ही होता है। इसके पीछे सोच आक्रामक के बजाय रक्षात्मक कदम उठाने की है जो उम्मीद पर आधारित हों। लेकिन यह हमारी पहली सहज वृत्ति नहीं है। मसलन, सिर्फ शेयरों के भाव धड़ाम होने की वजह से हम यह मानकर चलें कि इस गिरावट की वजह खत्म होते ही शेयर फिर से तेजी पकड़ लेंगे। यह शेयरों की खरीद का मौका है क्योंकि 'सामान्य' वक्त में शेयर बाजार में गिरावट का दौर आम तौर पर खरीदारी का वक्त होता है, न कि किनारे बैठ जाने और चिंतित होने का। लेकिन किसी ने कहा है कि शेयर बाजार में आपको नियमों का पालन करना चाहिए और इसी के साथ यह भी पता होना चाहिए कि कब इन नियमों का पालन नहीं करना है।

मैंने 1992 में हर्षद मेहता घोटाले के बाद से अब तक के हरेक शेयर बाजार क्रैश को करीब से देखा है। हरेक क्रैश के कारण अलग रहे थे लेकिन उन सबमें एक बात आम थी: पहली बड़ी गिरावट समस्या के पूर्ण प्रभाव को नहीं दर्शा पाती थी। आज भी निवेशक सदमे और तनाव में हैं लेकिन आशावादी बने हुए हैं। इस क्रैश के पहले निवेशक शेयरों के जिस ऊंचे भाव के अभ्यस्त थे वह अब भी उनके दिमाग पर हावी है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि हालात सामान्य होते ही शेयरों के भाव फिर से चढ़ जाएंगे। इस परिघटना को 'रेसेंसी बायस' यानी 'तात्कालिकता के प्रति झुकाव' कहा जाता है।

आशावाद की ही तरह हम इंसानों में एक और स्वाभाविक गुण होता है: हम केवल अपने कार्यों के तात्कालिक परिणामों यानी फर्स्ट-ऑर्डर प्रभावों को ही देख पाते हैं। फर्स्ट-ऑर्डर प्रभाव सरल होते हैं और कारण एवं उसके प्रभावों के बीच संबंध दृश्यमान होते हैं। अगर कोविड-19 महामारी के संदर्भ में देखें तो तीन हफ्तों के लॉकडाउन से इस वायरस का प्रसार धीमा हो पाना फर्स्ट-ऑर्डर प्रभाव है। लेकिन किसी महामारी या वित्तीय उथल-पुथल जैसे जटिल हालात में द्वितीयक एवं तृतीयक प्रभाव कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं और वे बाद में सामने आते हैं। लेकिन हम उनका पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं। एकदम इसी वजह से निवेशक मौजूदा बाजार क्रैश में पहली बड़ी गिरावट के बाद भी आशावादी बने रहे। यह 1992 में भी हुआ था जब अगस्त और सितंबर के बीच शेयर बाजार तेजी पकड़ने के बाद फिर से धराशायी हो गए थे। वर्ष 2000 में मई और जुलाई के बीच शेयर बाजार में गिरावट के पहले खूब तेजी रही थी। वर्ष 2008 में भी मार्च और मई के बीच शेयरों के भाव चढ़ने के बाद औंधे मुंह गिरे थे।

इन सभी मामलों में निवेशकों ने द्वितीयक एवं तृतीयक प्रभावों को नजरअंदाज किया था। वैसे मैं इस समय यह अनुमान नहीं लगाने जा रहा कि बाजार किस दिशा में जाएंगे। मेरा सिर्फ यह कहना है कि हम इस बार भी महामारी के द्वितीयक एवं तृतीयक प्रभावों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। अगर हम इन पर गौर नहीं करते हैं तो हम हालात की सच्चाई नहीं देख पाने से निराश ही होंगे। हमने काले धन पर लगाम लगाने के शुरुआती प्रभाव भी नहीं पैदा कर पाई नोटबंदी के बाद ऐसे प्रभावों के बारे में देखा है। इन प्रभावों ने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर डाला और द्वितीयक प्रभाव के तौर पर आय एवं मांग को खत्म ही कर दिया। हमें नोटबंदी और कुछ दूसरे नीतिगत गलतियों की भारी कीमत आर्थिक वृद्धि में 2.5 फीसदी की भारी गिरावट के तौर पर चुकानी पड़ी है।

सवाल है कि कोरोनावायरस से पैदा हुई महामारी के मामले में ये प्रभाव किस तरह के होंगे? यह वायरस के बारे में नहीं बल्कि इसके खात्मे के लिए छेड़ी गई जंग के आर्थिक प्रभावों के बारे में है। लॉकडाउन की घोषणा होते ही मजदूरों का बड़ी संख्या में शहरों को छोड़कर अपने गांवों की तरफ लौटना एक ऐसा द्वितीयक प्रभाव है जिसके बारे में मोदी सरकार ने न तो सोचा था और ही उसके लिए तैयार थी। मुझे आशंका है कि हमें लंबे समय तक मांग एवं आपूर्ति का झटका देखने को मिलता रहेगा। अभी हम यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि इसका स्वरूप कैसा होगा? स्वास्थ्य देखभाल एवं खानपान से संबंधित क्षेत्रों के अलावा लगभग हरेक क्षेत्र के इस आकस्मिक वैश्विक संकुचन से बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। हमने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं देखा है और हमें नहीं पता है कि प्रभावों की शृंखला कहां तक जा सकती है। अंग्रेजी के 'वी' आकार वाली आर्थिक बहाली को लेकर संदेह होने की यह सबसे बड़ी वजह है।

सबसे बुरी बात यह है कि हम अब भी सरकार की तरफ मुंह देख रहे हैं कि वह कुछ कदम उठाकर हालात सुधार देगी। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि कोविड-19 महामारी का प्रकोप फैलने के पहले ही हमारे सामने एक ऐसी सरकार थी जिसे आर्थिक वृद्धि में लगातार आ रही गिरावट को रोकने के लिए कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मैंने कई बार यह कहा है कि इस सरकार ने पिछली सरकारों जैसे तरीके ही आजमाए हैं और उसके साथ एक नया खराब पहलू भी जोड़ा है: अर्थव्यवस्था के दो सर्वाधिक उत्पादक वर्गों- कारोबार एवं परिवार के लिए लगातार नई-नई सामाजिक चिंताएं पैदा करते रहना। हमें यह ध्यान रखना होगा कि कारोबार ही रोजगार पैदा करते हैं एवं करों का भुगतान करते हैं और मांग बनाए रखने के अलावा करों के भुगतान में परिवारों की भूमिका काफी अहम होती है। जब यह सरकार आर्थिक पतन के परिचित हालात में दंभी, उदासीन एवं नासमझ बनी रही है तो एक महामारी के द्वितीयक एवं तृतीयक प्रभावों को लेकर इसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? हमने अभी तक का इसका रुख देखा है और यह बेहद खराब रहा है। खुद को बड़े, अप्रिय अचरजों के लिए तैयार रखिए और खुशकिस्मती से मिलने वाले राहत की उम्मीद कीजिए। हो सकता है कि यह सफर लंबा और उबड़-खाबड़ हो।

कोरोनावायरस के समय में कारोबारी सामाजिक दायित्व

जिंदगीनामा
कनिका दत्ता

कारोबारी जगत भले ही मजबूरी में निष्क्रिय पड़ा हो लेकिन उसका प्रचार तंत्र उतना ही सक्रिय नजर आ रहा है जितना कि कोरोनावायरस। उसकी सक्रियता की वजह है सरकार का वह निर्णय जिसके तहत उसने कोविड-19 से जुड़े व्यय को कारोबारी सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधि के अधीन लाने की अनुमति दी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) को दिए गए दान को सीएसआर व्यय माना जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंपनियों को एक ज्यादा बेहतर विकल्प दिया। यह था प्राइम मिनिस्टर्स असिस्टेंस ऐंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस यानी पीएम-केयर्स। देशव्यापी बंदी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को लेकर सरकार की नीति में गंभीर खामी के प्रायश्चित स्वरूप बनाए गए फंड की निंदा नहीं की जा सकती। यह ताली और थाली बजाने जैसी घटनाओं से तो बहुत बेहतर है।

प्रधानमंत्री मोदी की पहल से शुरू पीएम-केयर्स को एक अध्यादेश के जरिये प्रभावी बनाया गया। यह सन 1948 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित पीएमएनआरएफ से कई मायनों में बेहतर है। पहली बात तो यह कि ये पीएमएनआरएफ की तरह दान पर कर राहत देता है लेकिन इसमें उसकी तरह दानदाता की सकल आय के 10 फीसदी की सीमा नहीं है। दूसरा, कंपनियां जून के अंत तक इस फंड में राशि डाल सकती हैं और वित्त वर्ष 2020 के कर रिटर्न में राहत मांग सकती हैं। तीसरा, पीएम-केयर्स को दिया जाने वाला दान कंपनियों को गत वर्ष सितंबर में घोषित रियायती कम कॉर्पोरेट कर दर का लाभ लेने से नहीं रोकता। यह रियायती लाभ उन कंपनियों के लिए घोषित किया गया था जो अन्य कोई कर राहत नहीं प्राप्त करतीं।

गत वर्ष जुलाई में कंपनी अधिनियम में पुरातनपंथी बदलावों के बाद ये घोषणाएं कंपनियों को बहुत राहत प्रदान करने वाली हैं। उन बदलावों के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा अर्द्ध बाध्यकारी बनाए गए 'भुगतान करो या स्पष्ट करो' को राजग सरकार ने पूरी तरह अनिवार्य कर दिया था। इन संशोधनों के अधीन अनुपालन न करने वाली कंपनियों पर 50,000 रुपये से 25 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने की बात कही गई। इतना ही नहीं अधिकारियों को तीन वर्ष तक की जेल भी हो सकती है।

नियमों के मुताबिक कंपनियों को अपने पिछले तीन वर्ष के औसत लाभ का 2 फीसदी हर वर्ष विशिष्ट सीएसआर गतिविधियों पर व्यय करना होता है। 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक के टर्नओवर या 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की शुद्ध संपत्ति या पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक के मुनाफे वाली कंपनियों को अनुपालन के लिए तीन वर्ष का समय दिया गया है अथवा यह राशि सरकार द्वारा तय विशिष्ट फंड में चली जाएगी। वित्त मंत्री ने भले ही महात्मा गांधी के मुनाफे की सच्चाई और सामाजिक जवाबदेही का जिक्र किया हो लेकिन उक्त संशोधन प्रताड़ना के माहौल में इजाफा करने वाला है जो कारोबारियों को देश से बाहर जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। पीएम-केयर्स ने विभिन्न कंपनियों के सीईओ की सीएसआर की समस्या के लिए रामबाण औषधि प्रदान की है। आश्चर्य नहीं कि प्रधानमंत्री की घोषणा के तत्काल बाद कंपनियों के जनसंपर्क संभालने वाली टीमों ने अपनी कंपनी की कोविड-19 कार्य योजनाओं का ब्योरा पेश करना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रेस विज्ञप्तियों की बाढ़ आ गई। खबरें आने लगीं कि देश का कारोबारी जगत पीएम-केयर्स फंड में लाखों करोड़ों रुपये का दान कर रहा है, ठीक बॉलीवुड सितारों की तरह।

अगर पीएम-केयर्स इस राशि को समझदारीपूर्वक व्यय करता है तो यह दान बहुत अच्छा कदम है, भले ही इसकी प्रेरणा कहीं से भी आई हो। उदाहरण के लिए यदि इसका इस्तेमाल देशव्यापी स्तर पर आवश्यक कोविड-19 टेस्ट को सब्सिडी देकर सस्ता बनाने में किया जाता है तो इसे पैसे का सदुपयोग माना जाएगा। परंतु दो संदेह बरकरार हैं। पहला, यह सवाल उठा है कि जब आपदा राहत की फंडिंग के लिए 72 वर्ष पहले एक अलग फंड बनाया जा चुका था तो एक नए विशिष्ट फंड की क्या जरूरत है? इसकी एक कमजोर परिभाषा सरकार की ओर से आई है कि इस फंड का इस्तेमाल केवल कोविड-19 जैसी महामारियों से निपटने में किया जाएगा। यह भी कहा गया कि पीएमएनआरएफ की तरह यह व्यक्तिगत योगदान भी स्वीकार करता है।

यदि यह मान भी लिया जाए कि इस विशेष फंड के संभावित लाभ किसी राजनीतिक लक्ष्य पर भारी पड़ते हैं तो भी असहजता का दूसरा बिंदु शासन के इर्दगिर्द केंद्रित है। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष की तरह पीएम-केयर्स भी एक सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। लेकिन पीएमएनआरएफ का संचालन जहां प्रधानमंत्री कार्यालय के अफसरशाह करते हैं वहीं पीएम-केयर्स के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं तथा उसके सदस्य रक्षा, गृह और वित्त मंत्री हैं। राजनीतिक लोगों द्वारा इसका प्रबंधन परेशान करने वाला है। इससे यह संकेत मिलता है कि सीएसआर और सरकार के बीच एक जटिल रिश्ता तैयार हो रहा है जिसमें निगरानी की समस्या सामने आ सकती है। यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि पीएम-केयर्स की गतिविधियां भी पीएमएनआरएफ की तरह सार्वजनिक निगरानी में रहेंगी या नहीं? यदि सरकार कोविड-19 से लड़ाई में कारोबारी जगत का सार्थक सहयोग लेने को लेकर गंभीर थी तो वह केवल पैसे से इतर उन्हें विशिष्ट गतिविधियों में शामिल कर सकती थी जहां लाभ अधिक टिकाऊ होते। उदाहरण के लिए कुछ निजी कंपनियों और सरकारी बैंकों ने अपने सीएसआर प्रशासन को राज्य सरकारों द्वारा प्रवासियों को ठिकाना देने और पृथक्करण केंद्र बनाने की गतिविधियों में शामिल किया है। इसके अलावा बीमारी के प्रसार वाले नए इलाकों में चिकित्सा उपकरण और सुविधाएं मुहैया कराना भी कॉर्पोरेट जगत के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होता।

कानाफूसी

कोरोना- संदेश

अब आप इसे रचनात्मकता का शिखर कहें या पतन लेकिन कोलकाता में मिठाई की दुकानों की एक शृंखला ने कोरोनावायरस के नाम पर मिठाई ही बना डाली है। हिंदुस्तान स्वीट्स नाम की दुकान ने संदेश मिठाई को नोवेल कोरोनावायरस का आकार दिया है। लाल रंग के गोल संदेश पर कोरोनावायरस की तरह कांटे जैसी आकृतियां लगाई गई हैं। दुकान मालिक बंगाल की सबसे पसंदीदा मिठाई को इस महामारी से जोड़कर कठिन समय में लोगों का उत्साह बढ़ाना चाहते हैं। लोगों को मिठाई के साथ एक पर्चा भी दिया जा रहा है जिसमें कोरोना के खिलाफ नारे लिखे गए हैं और सुरक्षात्मक उपायों का जिक्र है। अब यह पेशकश वायरल हो चुकी है तो सवाल यह है कि क्या शहर के तमाम इलाकों में मौजूद इसकी शाखाओं में लोग उमड़ेंगे? जाहिर है प्रशासनिक अधिकारियों को यह बात पसंद नहीं आएगी।

सुरक्षात्मक उपाय

राजस्थान सरकार ने पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव अरविंद मायाराम के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है जो लॉकडाउन समाप्त होने के बाद प्रदेश के लिए आर्थिक खाका तैयार करने में मदद करेगी। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने भी नोबेल पुरस्कार से सम्मनित अभिजित बनर्जी और जिश्नू दास जैसे अर्थशास्त्रियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व निदेशक स्वरूप सरकार जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ, चिकित्सक सुकुमार मुखर्जी और पूर्व स्वास्थ्य सचिव जेवीआर प्रसाद राव की अध्यक्षता वाली एक समिति बनाई है। प्रदेश सरकार इस आठ सदस्यीय समिति के सुझावों के सहारे इस कठिन समय में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। उधर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान में अशोक गहलोत ने कोरोनावायरस की रोकथाम में अहम पेशकदमी की है।

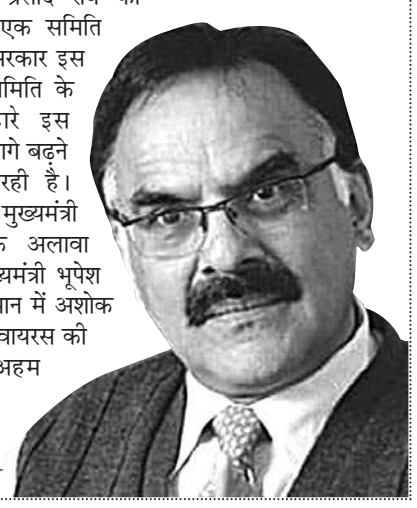

अरविंद मायाराम

आपका पक्ष

अर्थव्यवस्था पर नए सिरे से हो काम

दुनिया के करीब 190 देशों में कोरोनावायरस पहुंच चुका है। अमेरिका, इटली, फ्रांस और स्पेन में सबसे ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। स्थिति की गंभीरता देख केंद्र सरकार ने 21 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। हालांकि यह फैसला स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है, लेकिन इस फैसले का नकारात्मक असर उन कामगारों तथा दिहाड़ी मजदूरों को हो रहा है जो अपने गांव से काम की तलाश में शहरों में पलायन कर चुके थे। लॉकडाउन की वजह से वापस अपने गांव जाने के लिए मजदूरों में अफरातफरी का माहौल भी दिखा। हालांकि राज्य सरकार ने हालात को बेकाबू देखते हुए मजदूरों के लिए परिवहन की व्यवस्था भी की। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने किरायेदारों के पक्ष में एक महीने का किराया फिलहाल नहीं लेने के लिए मकान

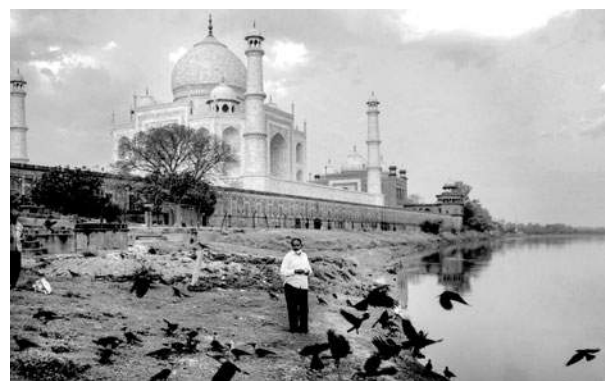

मालिकों को निर्देश भी जारी किए। इस 21 दिन के लॉकडाउन ने पहले से ही खराब दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है और आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप हो चुकी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी वैश्विक अर्थव्ययस्था के महामंदी की चपेट में आने के संकेत दिए हैं। इस तरह के संकेत भारतीय

आगरा सहित उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में हॉटस्पॉट सील किए गए -पीटीआई

अर्थव्यवस्था के लिए भी है क्योंकि विकासशील देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि तीन चीजों विदेशी निवेश, निर्यात तथा उपभोग पर निर्भर रहती है। लेकिन कोरोनावायरस ने मजबूत देशों की अर्थव्यवस्था को खस्ताहाल कर दिया है। वैश्विक महामंदी की वजह से वैश्विक मांग में कमी के चलते निर्यात पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। लॉकडाउन की वजह से कई उद्योग बंद पड़ गए हैं। लोगों के पास काम नहीं होने की वजह से घरेलू उपभोग में भारी कमी देखने को मिली है। ऐसी स्थिति को देखते हुए केंद्र तथा राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आर्थिक मसलों का सटीक जायजा लेकर अर्थशास्त्रियों की मदद से एक नए विकासवादी मॉडल पर काम शुरू किया जाए। पिछले दिनों केंद्र सरकार का अधिकतर ध्यान चुनाव और अन्य मसलों पर रहा था, लेकिन इस समय केंद्र सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने की होनी चाहिए।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

लॉकडाउन: एकजुटता की आड़ में हुड़दंग

कोरोनावायरस के खिलाफ जंग में देशवासियों को को एकजुट करने के प्रयास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल, रात 9 बजे, 9 मिनट के लिए अपने घरों की लाइट बंदकर एक दीया जलाने की अपील की थी। उक्त अवसर पर लगभग सभी घरों में दीये जलते हुए देखे गए। लेकिन इस बीच कई जगहों पर आतिशबाजी की गई और ढोल नगाड़े तक बजाए गए। कई जगहों पर तो लोग घरों से निकल कर सड़कों पर निकल आए। इस तरह की घटना ने इस मुहिम को संकट में डाल दिया। हम दीया या मोमबत्ती जलाकर सिर्फ उन लोगों के प्रति सम्मान जाहिर कर रहे थे जो ऐसे कठिन समय में भी अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन कई लोगों ने इसे पूरी तरह से हुड़दंग में बदल दिया। इस तरह की मानसिकता को बदलने की जरूरत है।

भूपेंद्र सिंह रंगा, कुरुक्षेत्र

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

नई दिल्ली | 9 अप्रैल 2020 गुरुवार बिज़नेस स्टैंडर्ड

कोरोना के मामले और मृतक संख्या बढ़ी

त्वरित इलाज के लिए घोषित तीन स्तरीय कार्ययोजना पर राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम शुरू किया गया

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बुधवार को बढ़कर 5,274 हो गए, जिनमें पिछले 24 घंटों के दौरान 485 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 149 हो गई। मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 4,714 है और 410 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक को दूसरी जगह भेजा गया है। कुल मामलों में 71 विदेशी नागरिकों के मामले भी शामिल हैं।

पिछले 24 घंटों के दौरान 25 नई मौत हुई हैं। इनमें महाराष्ट्र में 16, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और तमिलनाडु में दो-दो और आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति की मौत शामिल है।

कोरोनावायरस की वजह से महाराष्ट्र में सबसे अधिक 64 मौत हुई हैं। इसके बाद गुजरात एवं मध्य प्रदेश में 13-13 और दिल्ली में 9 लोगों की मौत हुई है। तेलंगाना, पंजाब, तमिलनाडु में 7-7 लोगों की मौत हुई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने संक्रमण की गति को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन को प्रभावी बताते हुए कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से स्थानीय लोगों को इस संक्रामक बीमारी के बारे में जागरूक करने तथा चिकित्सा उपायों को प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि संक्रमण के दायरे में आए लोगों के त्वरित इलाज के लिए घोषित तीन स्तरीय कार्ययोजना पर भी राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया गया है। संवाददाता सम्मेलन में गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी को देखते हुए सभी राज्य सरकारों को इस दिशा में तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

इस दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के वैज्ञानिक रमन आर गंगाखेडकर ने बताया कि देश में अब तक कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 1,21,271 परीक्षण हो चुके हैं। इनमें पिछले 24 घंटों के दौरान किए गए 13,345 परीक्षण शामिल हैं। उन्होंने बताया कि देश में आईसीएमआर की प्रयोगशालाएं बढ़कर 139 हो गई हैं जबकि निजी क्षेत्र की 65 प्रयोगशालाओं को भी कोविड-19 के परीक्षण करने की मंजूरी दे दी गई है।

चिकित्साकर्मी मरीजों की जांच के दौरान खुद की सुरक्षा के लिए भी बरत रहे हैं एहतियात *फोटो :पीटीआई*

- दुनिया भर में कोरोनावायरस के संक्रमण के मामले बढ़कर 13.8 लाख और मृतक 81,400 हुए
- ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ पर आरोप

लगाया कि वह चीन पर ज्यादा ध्यान दे रहा है और इस महामारी के दौरान गलत सलाह दे रहा है। उन्होंने कहा कि वह इस एजेंसी को अमेरिकी वित्तीय सहायता पर रोक लगाएंगे

- ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दूसरी रात आईसीयू में गुजारी और उनकी हालत स्थिर बनी हुई है

उप्र में हॉटस्पॉट सील

उत्तर प्रदेश में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित 15 जिलों के हॉटस्पॉट आज से सील कर दिए जाएंगे। प्रदेश के सभी जिलों को सैनिटाइज भी किया जाएगा, जिसके लिए फायर ब्रिगेड की मदद ली जाएगी।

प्रदेश सरकार के मुताबिक 15 जिलों- आगरा, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, सहारनपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, सीतापुर, फिरोजाबाद, शामली, बरेली, बस्ती, महराजगंज के हॉटस्पॉट के तौर पर चिह्नित स्थानों को बुधवार से ही सौ फीसदी सील किया जाएगा। कोरोना फैलने के सबसे ज्यादा मामले इन्हीं जिलों से आ रहे थे। प्रदेश में उन जिलों के ही हॉटस्पॉट को सील किया जा रहा है, जहां 6 अथवा अधिक कोरोना संक्रमण के मामले मिले हैं।

मप्र में एस्मा लागू

मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (ऐस्मा) लागू कर दिया। सरकार ने कोरोनावायरस के कारण लागू लॉकडाउन से बिगड़ी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक समिति का गठन भी किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 से निपटने के लिए तत्काल प्रभाव से ऐस्मा लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीमारी के प्रबंधन और नागरिक हित को ध्यान में रखते हुए सरकार यह कानून लागू कर रही है। *बीएस*

लॉकडाउन के बाद कामगारों का पलायन *फाइल फोटो*

गरीबी की चपेट में आएंगे 40 करोड़ : आईएलओ

सोमेश झा

कोविड-19 वायरस को नियंत्रित करने के लिए देश भर में लगाए गए कड़े लॉकडाउन के कारण करीब 40 करोड़ भारतीयों के गरीबी की चपेट में आने का जोखिम है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने हाल में जारी रिपोर्ट में ऐसा कहा है।

आईएलओ ने कोविड-19 और कार्य की दुनिया पर अपनी रिपोर्ट में कहा, 'भारत, नाइजीरिया और ब्राजील में लॉकडाउन और संक्रमण की रोकथाम के अन्य उपायों से असंगठित अर्थव्यवस्था में बड़ी तादाद में कामगार प्रभावित होंगे। भारत में करीब 90 फीसदी लोग अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करते हैं। ऐसे में करीब 40 करोड़ कामगारों के गरीबी की चपेट में आने का जोखिम है।'

आईएलओ के नीतिगत सुझाव

- सक्रिय राजकोषीय नीति, सहायक मौद्रिक नीति
- सभी को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना
- रोजगार अवसरों को बनाए रखने के लागू हों उपाय
- सवैतनिक अवकाश की पहुंच बढ़ाएं, घर से काम करने की व्यवस्था को अपनाया जाए

संगठन ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड के सूचकांक में भारत के मौजूदा लॉकडाउन के उपाय ऊपरी छोर पर रहे हैं। इससे असंगठित क्षेत्र के कामगार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और बहुत से कामगारों को ग्रामीण क्षेत्रों में वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

दरअसल आईएलओ ने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड के सूचकांक का इस्तेमाल करके एक चार्ट बनाया है। इसमें दिखाया गया है कि भारत ने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और ब्राजील एवं चीन जैसे अन्य देशों की तुलना में ज्यादा असंगठित कामगारों को लॉकडाउन में जकड़ा है।

आईएलओ ने कहा है कि लॉकडाउन और उससे संबंधित कारोबारी अवरोधों का कामगारों पर अचानक भारी असर पड़ा है। संगठन का अनुमान है कि इस महामारी से दुनिया भर में 19.5 करोड़ पूर्णकालिक नौकरियां जाने के आसार हैं। इसने कहा कि आवास एवं खाद्य सेवा, विनिर्माण, रियल एस्टेट, थोक एवं खुदरा कारोबार, वाहन मरम्मत जैसे क्षेत्रों को सबसे अधिक जोखिम में माना जा रहा है।

आईएलओ के मुताबिक दुनिया भर में करीब दो अरब लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इन लोगों में से अधिकतर उभरते और विकासशील देशों में हैं। इस अनुमान के मुताबिक भारत का दुनिया भर के असंगठित कामगारों में करीब 20 फीसदी हिस्सा है। नियमित रूप से रोजगार सर्वेक्षण करने वाली निजी एजेंसी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी ने कहा कि 5 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में बेरोजगारी की दर 23.4 फीसदी पर पहुंच गई।

भारत में लॉकडाउन से उल्टा प्रवास हुआ है। कामगार उद्योगों के बंद होने, स्वास्थ्य की चिंताओं और घर का किराया देने एवं अन्य जरूरतें पूरी करने में असमर्थ होने के कारण शहर छोड़कर गांव जा रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पांच से छह लाख कामगारों को पैदल घर जाना पड़ा क्योंकि उनके लिए परिवहन का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। लाखों श्रमिक अब भी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए रैन बसेरों में रह रहे हैं।

देश के सामने गंभीर चुनौतियां

पृष्ठ 1 का शेष

आगरा में कोरोनावायरस के सबस अधिक 22 हॉटस्पॉट हैं, जबकि गाजियाबाद में 13 और गौतम बुद्ध नगर तथा कानपुर में 12-12 इलाके हॉटस्पॉट केरूप में चिह्नित किए हैं। पूरे जिले के बाजय इन्हीं इलाकों में सख्ती से कर्फ्यू लागू किया जाएगा, पूरे जिले में नहीं। राज्य सरकार ने स्थानीय निवासियों और पेशेवरों को जारी किए गए सभी पास रद्द कर दिए हैं। इन इलाकों को सैनिटाइज किया जाएगा और सभी प्रभावित लोगों और कोरोना मरीजों के सीधे संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान की जाएगी।

विपक्षी दलों और संसद के अन्य दलों के साथ बैठक में मोदी ने कहा कि देश को कठिन फैसले लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हरेक जिंदगी को बचाना है। बीजू जनता दल के नेता पिनाकी मिश्रा ने कहा, प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन हटाया नहीं जा रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि कोरोना के प्रकोप के बाद अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रह जाएगी।' प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह की परिस्थिति उबर रही है, उससे संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है। मोदी ने कहा कि भारत उन चंद देशों में शामिल है, जो अब तक वायरस के प्रसार को थामने में सफल रहे हैं। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि परिस्थिति लगातार बदल रही है और हमें हर समय सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण देश गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है और सरकार इनसे निपटने के लिए प्रतिबद्ध है।

शीर्ष अधिकारियों ने उपायों के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। विपक्षी नेताओं ने स्वास्थकर्मियों के लिए पीपीई की कमी का मामला उठाया। कुछ नेताओं ने कहा कि सरकार को सेंट्रल विस्ता पर 20 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना से बचना चाहिए। इस बैठक में कई सुझाव आए। आजाद ने कहा कि मनरेगा मजदूरों को मुफ्त में किसानों की फसल काटने के काम में लगाया जाना चाहिएए कीटनाशकोंए उर्वरक और दूसरे कृषि उपकरणों को जीएसटी में छूट मिलनी चाहिए और लॉकडाउन हटाने या लगाने के बारे में क्षेत्रवार योजना बननी चाहिए।

लॉकडाउन के दौर में धीमा इंटरनेट

सचिन मामबटा और नेहा अलावधी

लॉकडाउन से पहले ज्यादा भीड़ वाले समय में यात्रियों का हुजूम सड़कों पर नजर आता था जिससे ट्रैफिक की समस्या दिखती थी। लेकिन अब घर से काम करने का विकल्प मिलने की वजह से इंटरनेट पर यह भीड़ जमा हो रही है। आजकल मोबाइल फोन डेटा की औसत रफ्तार में 20 फीसदी से अधिक की कमी आई है। वहीं फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की स्पीड में 8 फीसदी की कमी देखने को मिली है। यह विश्लेषण इंटरनेट की स्पीड पर डेटा मुहैया कराने वाली एक वैश्विक कंपनी ओकला के आंकड़ों पर आधारित है ।

इसने 5 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते के दौरान डेटा से जुड़ी जानकारी दी है और इसकी तुलना लॉकडाउन से पहले चार हफ्तों के दौरान की औसत गति से की गई है। इसमें यह जानकारी मिली कि 5 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में औसत मोबाइल डाउनलोड की स्पीड 20.9 फीसदी कम थी। वहीं अपलोड की स्पीड में 16.3 फीसदी की कमी थी। वहीं फिक्स्ड सेगमेंट में डाउनलोड स्पीड 8 फीसदी कम थी जबकि अपलोड स्पीड 9.9 फीसदी कम रही। मोबाइल ऐप्लिकेशन के इस्तेमाल पर

नजर रखने वाले बोबल एआई की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक लोग अपने दफ्तर के काम को पूरा करने, सामाजिक संवाद और मनोरंजन की जरूरतों के लिए इंटरनेट का ही सहारा ले रहे हैं।

नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और एमेजॉन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल में 82.6 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया ऐप्लिकेशंस पर 46.3 फीसदी ज्यादा वक्त दे रहे हैं। फिटनेस और शैक्षणिक ऐप की मांग भी बढ़ रही है क्योंकि लोग घर में व्यायाम करने और यूडेमी जैसे इंटरनेट आधारित संसाधनों के जरिये अपने लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्लिकेशंस के सक्रिय उपयोगकर्ताओं की तादाद में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जूम और हाउसपार्टी जैसे ऐप्लिकेशंस पर भी 71.1 फीसदी ज्यादा समय खर्च किया जा रहा है। वहीं सक्रिय उपयोगकर्ताओं की तादाद में भी 104.1 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है। दूसरे देशों में भी लॉकडाउन का अनुभव भी लगभग समान ही है। अमेरिका, चीन और यूरोप में इंटरनेट के इस्तेमाल में इजाफा देखा गया था। नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों को बाद में भारत सहित दुनिया भर में इंटरनेट पर लोड कम करने के लिए बैंडविड्थ कम करना पड़ा। ओकला ने एक बयान में कहा है, 'हम वैश्विक स्तर पर फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के लिए महीने भर की स्पीड में कमी देख रहे हैं और मार्च 2020 से ही मोबाइल ब्रॉडबैंड की स्पीड में भी कमी देखी गई है।'

चीन में भी इंटरनेट लोड में समान तरह की बढ़ोतरी देखी गई थी जहां पहली बार कोरोनावायरस का संक्रमण फैलने से लॉकडाउन की स्थिति बनी थी। हालांकि कंपनी के मुताबिक अब इसमें कमी आई है।

देश में चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए लॉकडाउन: विशेषज्ञ

सोमेश झा

कोरोनावायरस के कारण मचे हाहाकार के दौर में जिंदगी बनाम कारोबार की जोरदार बहस के बीच कई बुद्धिजीवियों, विश्लेषकों और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत को उन जिलों में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाना शुरू कर देना चाहिए जो कोविड-19 के संक्रमण से प्रभावित नहीं हैं। यह अलग मामला है कि राज्य और केंद्र तीन हफ्ते के लॉकडाउन को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रणव सेन का कहना है कि जो जिले इससे प्रभावित नहीं हैं, वहां लॉकडाउन हटा देना चाहिए लेकिन वहां से लोगों को दूसरी जगह जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। आंकड़े गवाह हैं कि क्यों इस तर्क में दम लग रहा है। लॉकडाउन अपने तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और कोविड-19 के 80 फीसदी से अधिक मामले 62 जिलों में पाए गए हैं। देश के 718 जिलों में से करीब 420 में इसका एक भी मामला नहीं है।

कोरोनावायरस महामारी

सेन का कहना है कि इन आंकड़ों का लाभ उठाकर भारत को सामान्य स्थिति बहाल करनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'इसमें कोई शक नहीं है कि अधिकांश प्रभावित इलाकों में देश के उच्च आय वाले शहरी इलाके शामिल होंगे और उत्पादन तथा खपत की स्थिति सामान्य होने में अधिक समय लगेगा।' सेन ने कहा कि भारत को आजीविका से इसकी शुरुआत करनी चाहिए और लॉकडाउन को अचानक पूरी तरह हटाना व्यावहारिक नहीं होगा।

आने वाले दिनों में सरकार की योजना ऐसे स्थानों की पहचान करने की होगी जहां कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें पूरे जिले को शामिल किया जाए। ज्यादा प्रभावित इलाकों में इसके प्रसार को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। एक अधिकारी ने कहा, 'इस तरह की त्वरित कार्रवाई से कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। कई समितियां इस संकट के समाधान के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही हैं और उनमें अर्थव्यवस्था सबसे अहम है। एक समिति ने हाल में अर्थव्यवस्था के उन पहलुओं पर विचार किया जिनमें कामकाज की अनुमति दी जा सकती है। दूसरे देशों की स्थिति का भी आकलन किया गया।'

इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव ऐंड सोशल मेडिसन के महासचिव डॉक्टर एएम कादरी ने कहा, 'जहां भी बड़ी संख्या में संदिग्धों की संख्या है या पुष्ट मामले हैं, उन्हें हॉटस्पॉट के रूप में परिभाषित करने की जरूरत है। हमें वहां लोगों के स्वास्थ्य पर नजर रखने की जरूरत है।' उन्होंने साथ ही कहा कि भारत को लॉकडाउन से काफी फायदा मिला है और उसे जल्दबाजी में इसे हटाकर इन फायदों से हाथ नहीं धोना चाहिए। कादरी ने कहा, 'ऐसा करना जरूरी नहीं होगा और इसे चरणबद्ध तरीके से हटाया जा सकता है। हम सभी जिलों को जोखिम के हिसाब से अलग-अलग श्रेणियों में रखना चाहिए और इसके मुताबिक ही लॉकडाउन हटाया जाना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में पूरी तरह लॉकडाउन होना चाहिए। इसी तरह ऐसे कार्यालयों को फिलहाल नहीं खोला जाना चाहिए जहां बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं और कंपनियों को घर से काम को प्रोत्साहन देना जारी रखना चाहिए। चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाने की योजना के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर और मॉल बंद रहने चाहिए।'

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को अगले दौर की तैयारी करते समय परिवहन व्यवस्था फिर से चालू करने के लिए भी एक योजना बनानी चाहिए। भारतीय प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर सेबेस्टियन मोरिस ने कहा, 'रेलवे और बसों को बंद करना भयावह हो सकता है। हमें परिवहन व्यवस्था को खोलने के लिए योजना बनानी चाहिए। हमें यह काम इस तरह करना होगा कि इससे नुकसान न हो और यह देखना पड़ेगा कि किस तरह की परिवहन व्यवस्था इसमें कारगर होगी। बसों के भीतर लोगों को खड़े होने की अनुमति होगी या नहीं। साथ ही हमें टैक्सी सेवाएं भी फिर से शुरू करने की जरूरत है।'

उदाहरण के लिए बसों में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए एक सीट खाली रखी जा सकती है जिससे लाखों प्रवासी कामगार शहरों में लौट सकें। मोरिस ने कहा कि यह इस समय अधिकारियों को स्थिति अपने हाथ में लेनी चाहिए और जरूरत के मुताबिक रणनीति बनाकर उन्हें लागू करना चाहिए।

चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले सप्ताह सही रणनीति तय करने के लिहाज से बेहद अहम होगा क्योंकि इस बीमारी के लक्षण दिखने में 14 दिन लगते हैं। उनका कहना है कि लंबे समय तक पूरे देश में लॉकडाउन लागू करना व्यावहारिक नहीं है। पीएसआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी, क्रिटिकल केयर ऐंड स्लीप मेडिसिन के चेयरमैन डॉक्टर जीसी खिलनानी ने कहा, 'लॉकडाउन का वास्तविक असर आने वाले हफ्ते में देखने को मिलेगा।' उन्होंने कहा कि आर्थिक दृष्टि से देखें तो देशव्यापी लॉकडाउन व्यावहारिक नहीं हो सकता है। खिलनानी ने सुझाव दिया कि जब तक देश में कोविड-19 की जांच के लिए आरटी-पीसीआर की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक राज्यों को तेजी से एंटीबॉडी जांच में तेजी लानी चाहिए जिसे भारतीय चिकित्सा शोध संस्थान ने हाल में मंजूरी दी है। आरटी-पीसीआर जांच की लागत 4,500 रुपये है जबकि एंटीबॉडी जांच की कीमत अमूमन 300 रुपये है। एंटीबॉडी जांच में विशेषज्ञता की जरूरत नहीं होती है और नतीजे एक घंटे में आ जाते हैं। खिलनानी ने कहा, 'इससे हमें बीमारी की थाह मिलेगी। एंटीबॉडी जांच के जरिये हमें पता चलेगा कि कितने लोगों में इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है।' खिलनानी का मानना है कि लॉकडाउन हटाने के लिए जांच बेहद जरूरी होगी। उनका कहना है कि भारत को अपने संसाधन ज्यादा प्रभावित जिलों में झोंकने होंगे और साथ ही टेस्टिंग किट की भी तैयारी करनी होगी।

दूसरी ओर वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और देश के जाने माने महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रकाश मूलियिल लोगों के एक वर्ग में प्रतिरोधक क्षमता (हर्ड इम्युनिटी) विकसित करने की वकालत करते हैं। इसके लिए समाज के एक तबके यानी युवाओं में इसका संक्रमण होने दिया जाए ताकि इसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जा सके। उन्होंने कहा, 'आप जांच की गति बढ़ा दें तब भी बीमारी तो होगी चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं।' उन्होंने कहा कि तीन हफ्ते के देशव्यापी लॉकडाउन से लोगों के बीच इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी और वे इससे बचने के तरीकों से वाकिफ होंगे और घरों से बाहर निकलकर भीड़भाड़ में जाने से परहेज करेंगे।

डॉक्टर मूलियिल ने कहा, 'भीड़भाड़ से बचिए, एकदूसरे से दूरी बनाने की कोशिश करिए। काम जारी रखना होगा, उद्योग को फिर से शुरू करना होगा, कृषि गतिविधियां फिर चालू करनी होंगी और साथ ही युवा इस संक्रमण से उबर जाएंगे। जब हर्ड इम्युनिटी विकसित हो जाएगी तब हम कह सकते हैं कि यह बीमारी खत्म हो गई है।' उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को अलग-थलग रखना होगा।

हालांकि सरकार हर्ड इम्युनिटी के सुझाव से सहमत नहीं है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'हर्ड इम्युनिटी का सहारा तभी लिया जा सकता है जब इसके लिए कोई टीका मौजूद हो। हम लोगों के एक वर्ग में संक्रमण की वकालत नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने चीन के वुहान के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। वहां संक्रमित लोगों की संख्या कम है और वे इसे काबू में करने में सफल रहे हैं। प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए कम लोगों की जरूरत हो सकती है।'

लेकिन अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए उद्योग को सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा। अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकर कौशिक बसु ने चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाने के उपाय सुझाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, 'यह वायरस कुछ समय तक रहेगा। सामाजिक दूरी या लॉकडाउन जरूरी है लेकिन हमें साथ ही धीरे-धीरे व्यापार, विनिमय और बाजारों को काम करने की अनुमति देनी होगी। अन्यथा खाद्य एवं जरूरी चीजों की आपूर्ति ठप हो जाएगी और रुपये बुरी तरह प्रभावित होगा।'

देश के ज्यादातर प्रभावित इलाकों में निश्चित ही संपन्न वर्ग वाले शहरी क्षेत्र शामिल हैं और इसलिए उत्पादन और खपत बहाल होने में भी उतना ही समय लगेगा

प्रणव सेन
पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद

काम चलते रहना चाहिए, उद्योग शुरू होने चाहिए, कृषि गतिविधियां जारी रहनी चाहिए। साथ ही साथ देश की युवा आबादी को इस संक्रमण से उबारा जाना चाहिए

जयप्रकाश मुलियिल
पूर्व प्रिंसिपल, सीएमसी वेल्लोर

हमें धीरे-धीरे व्यापार, बाजार और विनिमय शुरू करना होगा। वरना खाद्य और आवश्यक सामान की आपूर्ति में ठहराव आ जाएगा। मुद्रा में भारी अवमूल्यन हो सकता है

कौशिक बसु
प्रोफेसर, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी

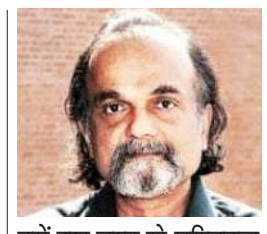

हमें इस तरह से परिवहन सुविधाएं खोलनी होंगी कि उनसे कोई विपरीत असर न हो। यह देखना होगा कि परिवहन का स्वरूप कैसा होगा। क्या लोगों को बसों में खड़े होने की इजाजत होगी

सेबस्टियन मोरिस
प्रोफेसर, आईआईएम